सोशल मीडिया से जुड़ें
Parivehan_Vishesh

RNI No :- DELHIN/2023/86499
DCP Licensing Number :
F.2 (P-2) Press/2023

www.newsparivahan.com

परिवहन विशेष

वर्ष 02, अंक 192, नई दिल्ली । शनिवार, 21 सितम्बर 2024, मूल्य ₹ 5, पेज 8

देश का पहला ट्रांसपोर्ट दैनिक समाचार पत्र

आज का सुविचार

जीवन हमेशा अपने सबसे अच्छे रूप में आने से पहले किसी संकट का इंतजार करता है।

03 भाजपा बिजली महंगी करने का षड्यंत्र जरूर रचेगी : आतिशी

06 कला, मनोरंजन और मीडिया में करियर के अवसर

08 राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और गति शक्ति...

डीटीओ हेड क्वार्टर में किया गया एक तकनीकी अधिकारी नियुक्त

संजय बाटला

नई दिल्ली। आपकी जानकारी हेतु बता दें कुछ दिन पहले दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा दिल्ली के अंदर पंजीकृत होने वाले व्यवसायिक गतिविधियों में प्रयोग होने वाले वाहनों की शाखा डीटीओ हेड क्वार्टर के पद पर गैर तकनीकी अधिकारी को नियुक्त कर दिया था और इस सबसे महत्वपूर्ण तकनीकी कार्यों में स्लग्न शाखा को तकनीकी अधिकारियो से मुक्त कर दिया था पर शुक्रवार दोपहर में ही आदेश जारी कर गैर तकनीकी अधिकारी के साथ एक तकनीकी अधिकारी को नियुक्त करने के आदेश जारी कर दिए। अब देखना यह होगा की शाखा में नियुक्त तकनीकी और गैर तकनीकी अधिकारी मिलकर कैसे कार्य करते हैं क्योंकि साथ ही दिल्ली परिवहन विभाग के आला अधिकारी 13 सितंबर 2024 को ही नए व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण के कार्य को वाहन डीलरो को सुपुर्द करने के आदेश कर चुके हैं और उसी आदेश मे नए व्यवसायिक वाहनों के पंजीकरण से संबंधित अन्य कामों को क्षेत्रीय शाखाओं में होने के भी निर्देश जारी किए हैं। ऐसे में पंजीकरण कार्यालय से पंजीकरण का कार्य समाप्त करने के बाद इस कार्यालय में दो अधिकारियो गैर तकनीकी अधिकारी को क्या कार्य सोपा और तकनीकी अधिकारी को क्या कार्य सोपा जाएगा बड़ा सवाल? परिवहन विभाग के आला अधिकारी द्वारा तकनीकी अधिकारी को इस शाखा में नियुक्त कर काफी हद तक दिल्ली की जनता की सुरक्षा का रास्ता वापिस बना दिया।

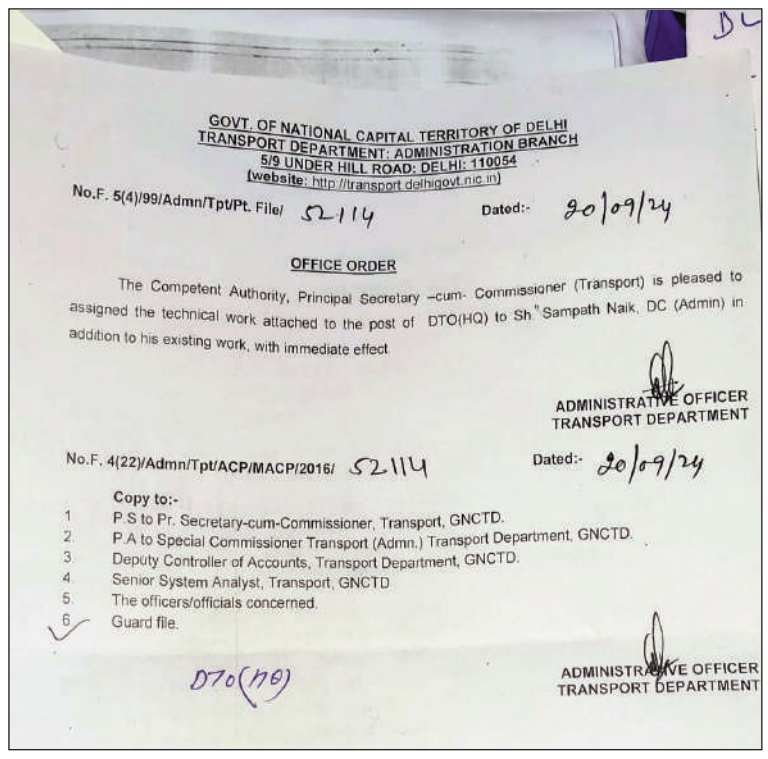

GOVT. OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI
TRANSPORT DEPARTMENT: ADMINISTRATION BRANCH
5/9 UNDER HILL ROAD: DELHI: 110054
(website: http://transport.delhigovt.nic.in)

No.F. 5(4)/99/Admn/Tpt/Pt. File/ 5214 Dated:- 20/09/24

OFFICE ORDER

The Competent Authority, Principal Secretary –cum- Commissioner (Transport) is pleased to assigned the technical work attached to the post of DTO(HQ) to Sh. Sampath Naik, DC (Admin) in addition to his existing work, with immediate effect.

ADMINISTRATIVE OFFICER
TRANSPORT DEPARTMENT

No.F. 4(22)/Admn/Tpt/ACP/MACP/2016/ 5214 Dated:- 20/09/24

Copy to:-
1. P.S to Pr. Secretary-cum-Commissioner, Transport, GNCTD.
2. P.A to Special Commissioner Transport (Admn.) Transport Department, GNCTD.
3. Deputy Controller of Accounts, Transport Department, GNCTD.
4. Senior System Analyst, Transport, GNCTD
5. The officers/officials concerned.
6. Guard file.

DTO(HQ)

ADMINISTRATIVE OFFICER
TRANSPORT DEPARTMENT

ट्रांसपोर्टरों के प्रतिनिधिमंडल ने क्षेत्र की शिकायतों पर चर्चा करने और समाधान का प्रस्ताव देने के लिए वरिष्ठ जीएसटी अधिकारियों से मुलाकात की

संजय बाटला

नई दिल्ली। 20 सितंबर 2024 को: परिवहन क्षेत्र के प्रमुख प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधिमंडल ने श्री शशांक प्रिय, आईआरएस (88), बोर्ड सदस्य, विशेष सचिव, और वित्तीय सलाहकार, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी), और श्री गौरव सिंह (आईआरएस), आयुक्त जीएसटी (नीति) के साथ नॉर्थ ब्लॉक में मुलाकात की। बैठक सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक माहौल में आयोजित की गई, जिसमें जीएसटी लागू होने के बाद ट्रांसपोर्टरों के सामने आने वाली विभिन्न परिचालन चुनौतियों के समाधान पर ध्यान केंद्रित किया गया। प्रतिनिधिमंडल ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं और अनुरोध किया कि परिवहन क्षेत्र में सुचारू संचालन की सुविधा के लिए इन्हें आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में शामिल किया जाए।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व श्री राजेंद्र कपूर, अखिल भारतीय मोटर एवं मोटर वाहन निगम के अध्यक्ष ने किया।

गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (रजिस्टर्ड) के अध्यक्ष श्री देवेंद्र सिंह, श्री अरबिंदर सिंह, श्री दीपक सचदेवा, श्री अरुण बंसल और श्री पुरुषोत्तम अग्रवाल जैसे प्रमुख सदस्यों ने पूरे भारत में निर्बाध, बाधा-मुक्त परिवहन प्रणाली के अपने दृष्टिकोण के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी और दिवंगत वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली के प्रति आभार व्यक्त किया।

बैठक के दौरान चर्चा की गई प्रमुख शिकायतें और प्रस्तावित समाधान इस प्रकार थे:

1. सीमित वाहन निरीक्षण:
2. आश्रयित निरीक्षण स्टेशन:
3. चालान हस्ताक्षर अनुपालन:
4. प्रेषक और प्राप्तकर्ता की जवाबदेही:
5. वाहन निरीक्षण की समय सीमा:
6. वाहन जब्ती से पहले दस्तावेजों की समीक्षा:
7. ई-वे बिल विस्तार समय में वृद्धि:
8. समाप्त हो चुके ई-वे बिलों के लिए दंड में ढील:
9. ई-वे बिल वैधता में छुट्टियों पर विचार:
10. रेलवे और बसों के माध्यम से अवैध माल परिवहन के लिए दंड:
11. भ्रष्टाचार रोकने के लिए कानून में संशोधन:
12. संदिग्ध माल की आंशिक उतराई का प्रावधान:

प्रतिनिधिमंडल ने श्री प्रिया से अनुरोध किया कि वे आगामी जीएसटी परिषद की बैठक में इन बिंदुओं को शामिल करें ताकि परिवहन उद्योग के हितों की रक्षा करने वाली निष्पक्ष, कुशल और पारदर्शी प्रणाली सुनिश्चित हो सके। श्री प्रिया ने प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया कि उनकी चिंताओं पर उचित विचार किया जाएगा। सादर,

राजेंद्र कपूर अध्यक्ष, ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (पंजीकृत)
9811159465, 9250549999

हाइवे प्लाजा में भूकम्प एवं अग्नि सुरक्षा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का आयोजन

परिवहन विशेष न्यूज

मथुरा : दिनाक़ 20 सितम्बर 2024 को उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के समन्वय से हाइवे प्लाजा और जयगुरुदेव इण्टर कॉलेज में भूकम्प एव अग्नि सुरक्षा पर राज्य स्तरीय मॉक एक्सरसाइज का अयोजन जिला प्रशासन और सिविल डिफेंस मथुरा के सहयोग से एक मेगा मॉक ड्रिल का सफल प्रदर्शन किया गया। सिविल डिफेंस मथुरा के पोस्ट वार्डन अशोक यादव ने बताया कि हाइवे प्लाजा मॉल में अचानक आग लगने की ख़बर मिलते ही सिविल डिफेंस मथुरा के उप नियंत्रक जसवंत सिंह और सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव सिंह अपने दल बल के साथ तत्काल मौके पर पहुंच कर अग्निशमन विभाग के साथियों के साथ मिलकर रेस्क्यू कार्य शुरू कर दिया गया गोल्डन सिनेमा हॉल हाइवे प्लाजा में फसे हुए आठ घायल लोगों को एम्बुलेंस के माध्यम से नजदीकी जिला हॉस्पिटल मथुरा में घायलों को भर्ती कराया गया राज्य स्तरीय मॉक ड्रिल में अपर जिलाधिकारी योगानंद पाण्डेय, तहसीलदार सदर राजकुमार यादव, उप नियंत्रक जसवंत सिंह, सहायक उप नियंत्रक जितेन्द्र देव, पोस्ट वार्डन अशोक यादव आपदा विशेषज्ञ सुशील कुमार, डिविजनल वार्डन भारत भूषण तिवारी, गिरिश, सैक्टर वार्डन राम सैनी, राजेश कुमार शिवहरे, गुलशेर, शुभम्-कुमार,

पवन, सुधाकर, नरेन्द्र मोहान, अभिषेक, सुनीता, सेलेश खण्डेलवाल जितेन्द्र, मुकेश शर्मा, रोहिताश, सुनैना, जवर सिंह, राकेश, विक्रम, रिंकी, एव एसडीआरएफ,एनडीआरएफ, फायर विभाग, मेडिकल टीम, ट्रेफिक पुलिस, और थाना हाईवे प्रभारी सभी लोगो ने मेगा मॉक ड्रिल को सफल बनाने में सहयोग प्रदान किया।

आसान होगा सफर: अब महादेव की काशी से गोरक्षनगरी के लिए भी चलेंगी इलेक्ट्रिक बसें, दिसंबर से भरेंगी फर्राटा

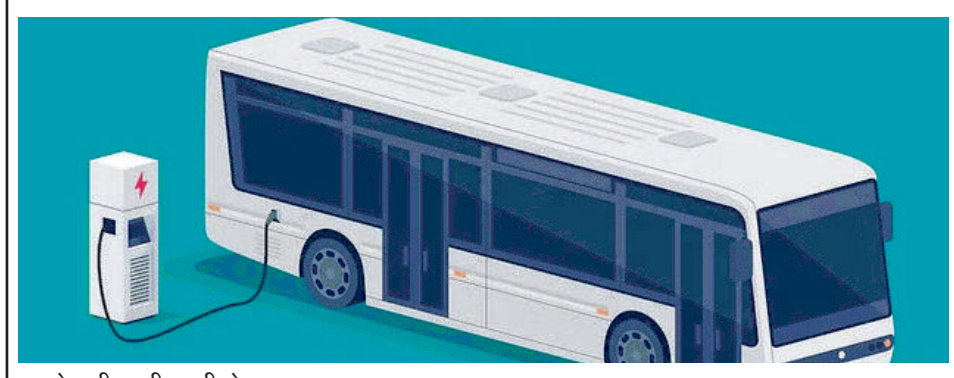

महादेव की नगरी काशी से गोरक्षनगरी तक का सफर अब आसान होगा। परिवहन निगम की ओर से अब वाराणसी से गोरखपुर के लिए भी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी।

अब गोरखपुर से अयोध्या और वाराणसी के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलेंगी। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा 20 इलेक्ट्रिक बसों के भेजे गए प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। दिसंबर के पहले सप्ताह में इन बसों के जनपद में आने की उम्मीद जताई जा रही है।

परिवहन निगम के अधिकारियों ने बताया कि बसों को नौ रूटों पर चलाया जाएगा। सभी इलेक्ट्रिक बसें गोरखपुर से ही चलेंगी। अभी तक परिवहन की साधारण बसों से लोग अयोध्या, वाराणसी आदि जगहों की यात्रा करते थे। इन बसों के आ जाने से लोगों के पास एसी इलेक्ट्रिक बसों का विकल्प भी मिल जाएगा। यह बसें लोगों का सोनौली, आजमगढ़, गाजीपुर, महराजगंज, सिद्धार्थनगर, पडरौना, तमकुही रोड, देवरिया व भागलपुर से जोड़ेंगी। इलेक्ट्रिक बसें दिसंबर से सड़कों पर फर्राटा भरने लगेंगी।

राजघाट क्षेत्र में रात 10 से सुबह 8 बजे तक चलेंगी बसें

राजघाट क्षेत्र में पितृपक्ष के महीने तक बसों का संचालन रात 10 बजे से सुबह 8 बजे तक हो सकेगा। पुलिस कमिश्नर ने बृहस्पतिवार को ये निर्देश दिए। हालांकि वाहन सड़क पर नहीं खड़े होंगे। दरअसल राजघाट क्षेत्र में बस पर रोक से यात्रियों के न आने से व्यापारी चिंतित थे। उन्होंने अपनी समस्या विधायक डॉ. नीलकंठ तिवारी को बताई।

विधायक से बातचीत के बाद पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया कि रात्रि 10 बजे से सुबह 8 बजे तक बसों का संचालन किया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर जाने हेतु भी यात्री राजघाट-प्रह्लादघाट मार्ग का उपयोग करते हैं। इस वजह होटल, पेइंग गेस्ट हाउस, होम स्टे, रेस्टोरेंट जैसे व्यापार काफी बढ़ चुका है। मुलाकात करने वालों में नलिन नयन मिश्र, लकी भारद्वाज, बालाजी राय, दिलीप कुशवाहा, अजय साहनी, दुर्गा साहनी रहे।

टेंपल्स ऑफ लिबरलाइजेशन एंड वेलफेयर एलाइड ट्रस्ट (पंजीकृत)

TOLWA

website : www.tolwa.in
Email : tolwadelhi@gmail.com
bathlasanjaybathla@gmail.com

रजिस्टर्ड अंडर सैक्शन 60 विद रजिस्ट्रेशन नंबर (152/02-03-2020), एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर उद्यम -डीएल - 0026470, नीति आयोग रजिस्ट्रेशन नंबर वीओ/एनजीओ/0303274/25-01-2022 दर्पण

रजिस्टर्ड कार्यालय :- 3, प्रियदर्शिनी अपार्टमेंट, ए -4 पश्चिम विहार, न्यू दिल्ली 110063
कॉरपोरेट कार्यालय :- 529, समयपुर, मेंन बवाना रोड, नियर बैंक ऑफ़ बड़ौदा दिल्ली 110042

पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पर चलती ट्रेन के आगे कूदी महिला, खोया दाहिना हाथ; सेवाएं रहीं बाधित

दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर शुक्रवार को ट्रेनों की आवाजाही में करीब 15-20 मिनट की देरी हुई। दरअसल पीतमपुरा रेलवे स्टेशन पर दोपहर करीब 230 बजे एक महिला चलती ट्रेन के सामने कूद गई। इसमें महिला का दाहिना हाथ कट गया। अधिकारियों ने बताया कि इस घटना की जांच की जा रही है कि क्यों वह ट्रैक पर कूदी थी?

नई दिल्ली। पीतमपुरा स्टेशन पर चलती मेट्रो ट्रेन के सामने कूदने से 53 वर्षीय एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। अधिकारियों ने बताया कि शुक्रवार दोपहर हुई इस घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया। घटना के कारण दिल्ली मेट्रो की रेड लाइन पर सेवाएं कुछ देर के लिए बाधित रहीं। रेड लाइन दिल्ली के रिठाला को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में शहीद स्थल (नया बस अड्डा) से जोड़ती है।

एक अधिकारी ने बताया कि मेट्रो पुलिस को दोपहर 2.23 बजे एक महिला के पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पर ट्रेन के सामने कूदने की सूचना मिली। गंभीर रूप से घायल महिला को मेट्रो कर्मचारियों ने रोहिणी के बीएसए अस्पताल में भर्ती कराया। अधिकारी ने बताया कि पुलिस कर्मियों की एक टीम अस्पताल पहुंची और पाया कि घटना में उसका दाहिना हाथ कट गया है।

महिला के कूदने से 15-20 मिनट की हुई देरी

अधिकारी ने बताया कि महिला का अस्पताल में इलाज चल रहा है। उन्होंने बताया कि उसके परिवार के सदस्यों को सूचित कर दिया गया है और मामले की आगे की जांच जारी है। डीएमआरसी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दोपहर करीब 2:30 बजे रेड लाइन पर पीतमपुरा मेट्रो स्टेशन पर महिला ट्रैक पर कूद गई थी, जिससे 15 से 20 मिनट की देरी हुई। अधिकारी ने बताया कि महिला को ट्रैक से हटाने के बाद सामान्य सेवाएं बहाल कर दी गईं।

तेजी से बढ़ रहा प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत का आंकड़ा, स्वास्थ्य विभाग अलर्ट

गाजियाबाद में प्रसव के दौरान महिलाओं की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल से 8 अक्टूबर तक 10 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग ने मौत रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है। इस अभियान के तहत शहरी और देहात क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया जाएगा।

गाजियाबाद। प्रसव के दौरान अथवा बाद में अधिक रक्त स्राव होने और हीमोग्लोबिन कम होने से गाजियाबाद में महिलाओं की मौत का आंकड़ा तेजी से बढ़ रहा है। अप्रैल से 8 अक्टूबर तक 10 महिलाओं की मौत हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग ने मौत रोकने के लिए एक विशेष अभियान चलाने का निर्णय लिया है।

इस अभियान के तहत शहरी और देहात क्षेत्र में गर्भवती महिलाओं का सर्वे किया जाएगा। आशा, एएनएम और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता प्रतिदिन अपने-अपने क्षेत्र की गर्भवती महिलाओं की सेहत का हाल-चाल पूछने के लिए उनके घर जाएंगी। नियमित टीकाकरण के साथ गर्भवती महिलाओं को बेहतर खान-पान के बारे में भी जागरूक किया जाएगा ।प्रत्येक माह की 1 ,9 , 16 और 24 को होने वाले विशेष आयोजन के तहत प्रत्येक गर्भवती महिला के स्वास्थ्य की निशुल्क जांच कराई जाएगी।

इस जांच में यह भी पता चल जाएगा की महिला में खून की कमी है अथवा नहीं ,और यदि खून की कमी होगी तो तुरंत महिला को खून चढ़ाया जाएगा। प्रसव के लिए महिलाओं को जिला अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा।

पिछले 6 महीने में 7000 से अधिक महिलाओं के प्रसव संस्थागत हुए हैं। इनमें जिला महिला अस्पताल में सबसे अधिक प्रसव हो रहे हैं ।कई बार सिजेरियन प्रसव के दौरान चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों की लापरवाही की वजह से भी महिला की मौत हो रही है। पिछले साल ऐसे 32 मामलों में जांच करने के बाद लापरवाही उजागर हुई है। सीएमओ डॉक्टर भवतोष शंखधर ने बताया कि प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान को मजबूती से लागू करने हुए घर-घर जाकर गर्भवतियों का पता लगाया जाएगा।

सभी गांठें नहीं होती हैं ब्रेस्ट कैंसर, करती हैं इन बीमारियां की ओर इशारा

आजकल ज्यादातर महिलाएं ब्रेस्ट कैंसर की चपेट में आ रही हैं। इसके चलते इसको लेकर जागरूकता महिलाओं के बीच बढ़ी है। महिलाओं अकसर खुद घर पर ही अपने ब्रेस्ट में गांठ के लिए चेक करती रहती हैं। ब्रेस्ट में किसी तरीका का परिवर्तन बहुत चिंता का कारण बन सकता है। ये तो समझ में आता है। लेकिन हर बार ब्रेस्ट में परिवर्तन की वजह ब्रेस्ट कैंसर नहीं होती हैं।

ब्रेस्ट में कोई भी लक्षण, जैसे कि ब्रेस्ट में गांठ, निपल से स्राव या ब्रेस्ट में दर्द, आदि की जांच करके इसकी सही वजह एक्सपर्ट ही बता सकते हैं। आपको बता दें ब्रेस्ट के जुड़ी और भी लक्षण होते हैं जो ब्रेस्ट कैंसर की ओर नहीं बल्कि किसी और बीमारी की ओर इशारा करते हैं। आइए आपको बताते हैं इनके बारे में....

फाइब्रोएडीनोमा

फाइब्रोएडीनोमा ब्रेस्ट का सबसे आम किस्म का ट्यूमर है। ज्यादातर ये 15 से 35 साल की उम्र के लोगों में होते हैं। ब्रेस्ट examination के दौरान में ये अक्सर एक सख्त, गोल, चिकनी और रबड़ जैसी स्तन गांठ के रूप में दिखाई देते हैं। कई फ़ाइब्रोएडीनोमा का समय-समय पर अल्ट्रासाउंड करके इलाज किया जा सकता है। ये भविष्य में स्तन कैंसर के खतरे को नहीं बढ़ाते हैं।

ब्रेस्ट सिस्ट

कभी-कभी, ब्रेस्ट में सिस्ट विकसित हो सकते हैं। सिस्ट तरल पदार्थ से भरे सेल्स होते हैं। ये breast tissue में गांठों या मैमोग्राम पर पाई जा सकती हैं। वे हमेशा लक्षण पैदा नहीं करते हैं, लेकिन जैसे- जैसे सिस्ट बढ़ते हैं ब्रेस्ट में दर्द और sensitivity पैदा होती हैं। ये 35 से 60 साल की उम्र के बीच आम हैं, और पीरियड्स के साथ उतार-चढ़ाव हो सकता है। वहीं ब्रेस्ट में सिस्ट ब्रेस्ट कैंसर का खतरा नहीं बढ़ता है।

मास्टिटिस

ये ब्रेस्ट tissue में एक तरह की सूजन है जो ब्रेस्ट में दूध नलिकाओं के ब्लॉक होने से या बैक्टीरिया के कारण होती है। यह आमतौर पर ब्रेस्टफीड करवाने वाली महिलाओं को प्रभावित करता है, लेकिन यह उन महिलाओं में भी हो सकता है जो ब्रेस्टफीड नहीं करवाती हैं। सूजन से ब्रेस्ट में दर्द, सूजन, गर्मी और लालिमा होती है। मास्टिटिस का इलाज एंटीबायोटिक दवाओं और दर्द निवारक दवाओं से किया जा सकता है।

पैपिलोमा

पेपिलोमा milk duct में एक वृद्धि है और यह निप्पल डिस्चार्ज के रूप में प्रकट हो सकता है। यह निप्पल के पीछे या बगल में एक छोटी गांठ के रूप में भी मौजूद हो सकता है। बायोप्सी यह समझने में मदद कर सकती है कि क्या पेपिलोमा का इलाज करने की जरूरत है या नहीं , क्योंकि कभी-कभी उनमें असामान्य कोशिकाएं हो सकती हैं जो ब्रेस्ट कैंसर के खतरे को बढ़ा सकती हैं। वहीं इसका इलाज duct के बढ़े हुए आकार पर भी निर्भर करता है, यदि कई गांठें हैं या यदि वे लक्षण पैदा कर रहे हैं। पेपिलोमा को हटाने के लिए सर्जरी भी की जाती है।

असामान्य हाइपरप्लासिया (Atypical hyperplasia)

इसमें ब्रेस्ट की दूध नलिकाओं (milk ducts) में असामान्य कोशिकाओं यानी सेल्स बनते है। बता दें एटिपिकल हाइपरप्लासिया कोई कैंसर नहीं है, लेकिन इससे जरूर ब्रेस्ट कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। इस कारण से, कभी-कभी उस क्षेत्र को सर्जरी से हटा दिया जाता है। अक्सर, एक्सपर्ट्स कैंसर के खतरे को कम करने के लिए उस क्षेत्र को सर्जरी से हटा दिया जाता है। वहीं इसके इलाज के लिए खूब सारी screenings और दवाएं लेने की सलाह दी जाती है।

कामकाजी महिलाओं के लिए आवाज उठाने वाली क्लॉडिया गोल्डिन को अर्थशास्त्र का नोबेल प्राइज

हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में स्त्री-पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 'रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज' के महासचिव हैंस एलेग्रेन ने इस पुरस्कार की घोषणा की है। गोल्डिन इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली तीसरी महिला हैं। उन्होंने पुरुषों और महिलाओं के वेतन में अंतर के कारणों को समझने के लिए काफी शोध किया है।

अर्थशास्त्र विज्ञान क्षेत्र में पुरस्कार विजेता का चयन करने वाली समिति के प्रमुख जैकब स्वैनसन ने कहा- ''श्रम बाजार में महिलाओं की भूमिका को समझना समाज के लिए महत्वपूर्ण है। क्लॉडिया गोल्डिन के अभूतपूर्व शोध के लिए धन्यवाद, अब हम अंतर्निहित कारकों के बारे में और अधिक जानते हैं तथा भविष्य में किन बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता हो सकती है।"

गोल्डिन ने अमेरिका के 200 साल के इकनॉमिक इतिहास में महिलाओं की भागीदारी का अध्ययन किया। पुरस्कार समिति के सदस्य रैंडी एच. ने कहा कि गोल्डिन समाधान पेश नहीं करती हैं, लेकिन उनका शोध नीति निर्माताओं को समस्या से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। उन्होंने कहा- ''गोल्डिन (श्रम बाजार में) लैंगिक भेदभाव के मूल स्त्रोत पर ध्यान आकर्षित करती हैं और यह कि समय के साथ तथा विकास के क्रम में इसमें किस तरह बदलाव आया। इसलिए, कोई एक नीति काफी नहीं है।"

एलेग्रेन ने बताया कि पुरस्कार की घोषणा के बाद 77 वर्षीय गोल्डिन ''आश्चर्यचकित और बेहद खुश" हुईं। नोबेल पुरस्कार के तहत विजेता को 10 लाख डॉलर का पुरस्कार दिया जाता है। दिसंबर में ओस्लो और स्टॉकहोम में होने वाले पुरस्कार समारोहों में विजेताओं को 18 कैरट का स्वर्ण पदक और एक डिप्लोमा भी दिया जाता है।

बता दें कि क्लाउडिया गोल्डिन फिलहाल हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स की प्रोफेसर के तौर पर कार्य कर रही हैं। वह एनबीईआर के जेंडर इन द इकोनॉमी ग्रुप की को-डायरेक्टर भी हैं। क्लाउडिया गोल्डिन 1989-2017 के दौरान एनबीईआर के अमेरिकन इकोनॉमिक प्रोग्राम की डेवलपमेंट डायरेक्टर थीं। उन्होंने कहा कि डिटेक्टिव होने के पीछे सोच ये रहती है कि आप खुद से सवाल पूछते रहें और उनके सवालों के जवाब मिलने तक कार्यरत रहें. आज भी उनके अंदर ये सोच जिंदा है।

वजन कम करने से लेकर पाचन स्वस्थ रखेगी मिक्स दाल, जानिए इसके बेशुमार फायदे

दाल का सेवन करना स्वास्थ्य के लिए बेहद फायदेमंद होता है इसलिए घरों में एक बार इसे जरुर खाते हैं। दाल खाने से हड्डियां मजबूत होती हैं, पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है। पहले समय में दालों को मिक्स करके बनाया जाता था इस तरह की दाल स्वादिष्ट होने के साथ-साथ पोषक तत्वों को बढ़ाती है। मिक्स दाल को कई दालों के साथ मिलाकर बनाया जाता है जैसे अरहर, मूंग, चना, मसूर और उड़द की दाल इसमें शामिल की जाती है। इन सारी दालों में कई सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जैसे प्रोटीन, कैल्शियम, कार्बोहाइड्रेट और फाइबर। इस दाल का सेवन करने से शरीर को ताकत मिलती है और शरीर की कमजोरी भी दूर होती है। तो चलिए आज आपको बताते हैं कि मिक्स दाल खाने से शरीर को और क्या-क्या फायदे होंगे....

वजन होगा कम

मिक्स दाल का सेवन करने से वजन कम करने में भी सहायता मिलती है। इसमें मौजूद फाइबर पेट को लंबे समय तक भरकर रखता है जिससे भूख कम लगती है। इससे खाने की इच्छा शक्ति भी कम होती है जिससे वजन कम करने में सहायता मिलती है। मिक्स दाल में कैलोरी की मात्रा भी काफी कम मौजूद होती है। ऐसे में यदि आप वजन कम करना चाहते हैं तो इसे अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं।

बीमारियों से होगा बचाव

इसके अलावा मिक्स दाल खाने से डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल जैसी बीमारियां भी नियंत्रण में रहती हैं। इन दालों में फैट कम मात्रा में पाया जाता है जिससे दिल संबंधी बीमारियोंका जोखिम कम होता है। इसमें मौजूद फाइबर हार्ट को हेल्दी रखने में भी मदद करता है।

हड्डियां बनेगी मजबूत

मिक्स दाल में कैल्शियम काफी अच्छी मात्रा में पाया जाता है यह हड्डियों को मजबूत बनाने और मांसपेशियों में होने वाले दर्द को भी कम करने में भी मदद करती हैं। मिक्स दाल खाने से कमजोरी दूर होती है और शरीर को ताकत मिलती है।

पाचन रहेगा स्वस्थ

यह पाचन संबंधी बीमारियों को दूर करने के लिए भी बेहद लाभकारी मानी जाती हैं। इसका सेवन करने से पेट साफ होता है और कब्ज की समस्या में भी आराम मिलता है। इसके अलावा मिक्स दाल खाने से अपच, गैस, बदहजमी और एसिडिटी से भी राहत मिलती है।

इम्यूनिटी बनेगी मजबूत

मिक्स दाल का सेवन करने से मौसमी बीमारियों से भी बचाव होता है क्योंकि इसमें विटामिन-सी काफी अच्छी मात्रा में मौजूद होता है। यह शरीर की इम्यूनिटी बढ़ाकर बीमारियों से बचाने में मदद करता है। मिक्स दाल खाने से वायरल बीमारियों का खतरा कम होता है और शरीर लंबे समय तक स्वस्थ रहता है।

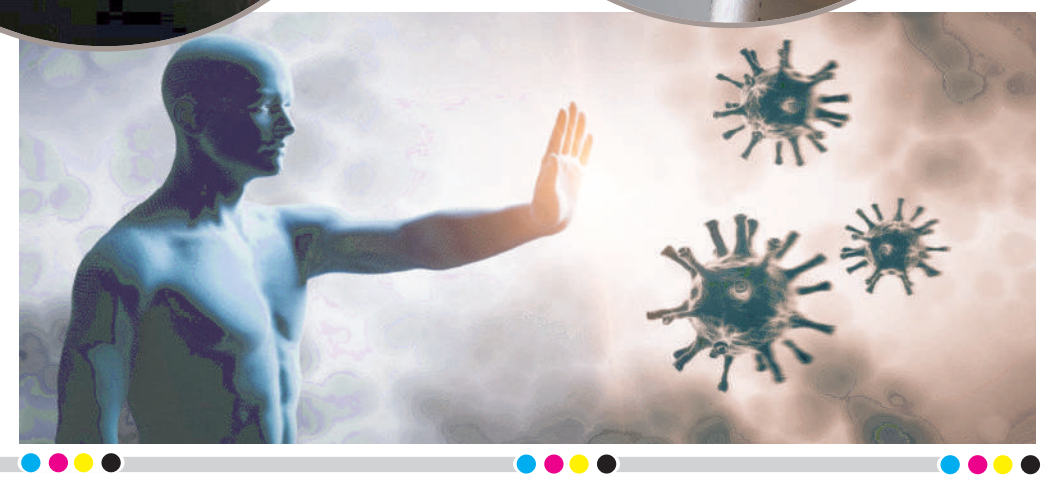

राष्ट्रीय पार्टी ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक को सरकारी आवास आवंटित करे केंद्र सरकार, यह सुविधा नहीं, साधन है- राघव चड्ढा

''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक इस्तीफा देने के बाद सीएम के रूप में मिली सभी सुविधाएं जल्द त्याग देंगे- राघव चड्ढा

सुषमा रानी

नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुचारू रूप से अपना कामकाज करने के लिए केंद्र सरकार से सरकारी आवास आवंटित करने की अपील की है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा नहीं, बल्कि साधन है। अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। लिहाजा वह मुख्यमंत्री के रूप में मिली आवास समेत सभी सुविधाएं जल्द त्याग देंगे। चूंकि ''आप'' एक राष्ट्रीय पार्टी है और नियमानुसार, हर राष्ट्रीय पार्टी को देश की राजधानी दिल्ली में एक कार्यालय और राष्ट्रीय संयोजक को एक सरकारी आवास मिलता है। देश में कई राष्ट्रीय पार्टियां हैं और उनके राष्ट्रीय संयोजक को कार्यालय के साथ एक सरकारी आवास मिला भी है। उन्होंने कहा कि 10 साल दिल्ली का मुख्यमंत्री होने के बावजूद अरविंद केजरीवाल के पास अपना कोई घर नहीं है। इसलिए पार्टी आवास एवं शहरी मामलों के नोडल मंत्रालय को पत्र भी लिख रही है, ताकि जल्द से जल्द एक सरकारी आवास आवंटित हो सके।

आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे से पूरे देश में एक बात साबित हो गई है कि केजरीवाल को सीएम की कुर्सी, पद या पावर का लालच नहीं है। उन्हें सिर्फ देश की राजनीति में नैतिकता और मर्यादा का लालच है। केजरीवाल ने इसी नैतिकता और मर्यादा को ऊपर रखते हुए अपनी ईमानदारी की अग्निपरीक्षा देने का फैसला दिया। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां एक चपरासी भी अपनी नौकरी से इस्तीफा नहीं देता और अपनी कुर्सी से चिपका रहता है। इस कलयुग में अरविंद केजरीवाल ने दो बार मर्यादा और नैतिकता को मानते हुए अग्निपरीक्षा दी और दो बार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा दिया। पहली बार उन्होंने 49 दिन की सरकार चलाने के बाद नैतिकता और मर्यादा को महत्व देते हुए इस्तीफा दे दिया था।

राघव चड्ढा ने कहा कि आम आदमी पार्टी इस देश में सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली पार्टी है। 10 साल में हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला। कानून के अनुसार, जब किसी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दिया जाता है तो उसे दो साधन दिए जाते हैं। पहला, उसे अपना काम करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी में एक कार्यालय दिया जाता है। दूसरा, राष्ट्रीय पार्टी के संजोयक को एक सरकारी आवास दिया जाना चाहिए। इस देश में समय-समय पर कई राजनैतिक पार्टियां बनीं और उनके राष्ट्रीय संजोयजक को दिल्ली में एक सरकारी आवास दिया गया। यह सब चुनाव आयोग के कानून के तहत होता है। आज उसी कानून का हवाला देते हुए हम केंद्र सरकार से विनती करेंगे कि मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद ''आप'' के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को एक सरकारी आवास दिया जाए।

राघव चड्ढा ने कहा कि इस देश में करीब 6 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। भाजपा, जिसके अध्यक्ष जेपी नड्डा को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते एक सरकारी आवास दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, बसपा की अध्यक्षा मायावती, सीपीएम और एनपीपी के राष्ट्रीय अध्यक्षों को दिल्ली में सरकारी आवास मिला हुआ है। इसलिए हम चाहते हैं कि देश की छठीं राष्ट्रीय पार्टी होने के नाते आम आदमी पार्टी को भी जो साधन मिलने चाहिए, वे मुहैया कराए जाएं। इस संदर्भ में आम आदमी पार्टी आवास और शहरी मामलों के नोडल मंत्रालय को पत्र लिख रही है। हम अनुरोध करेंगे कि अरविंद केजरीवाल को जल्द से जल्द यह साधन मुहैया कराए जाएं। उम्मीद है कि हमें सरकारी आवास लेने के लिए लंबी लड़ाई नहीं लड़नी पड़ेगी और केंद्र सरकार राजनीति से प्रेरित फैसले नहीं लेगी। चूंकि अरविंद केजरीवाल को अपना आवास खाली करना है। इसलिए जल्द से जल्द जो हमारा अधिकार है, वह हमारी पार्टी को दिया जाए।

दिल्लीवाले सर्दियों में 'वर्क फ्रॉम होम' के लिए रहें तैयार, सरकार ने विंटर एक्शन प्लान को किया फाइनल

दिल्ली सरकार ने सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए विंटर एक्शन प्लान तैयार किया है। इस योजना के तहत 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की ड्रोन के जरिये निगरानी की जाएगी। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस वर्ष के विंटर एक्शन प्लान में हॉटस्पॉट वाहन और धूल प्रदूषण वर्क फ्रॉम होम आदि का प्रावधान है।

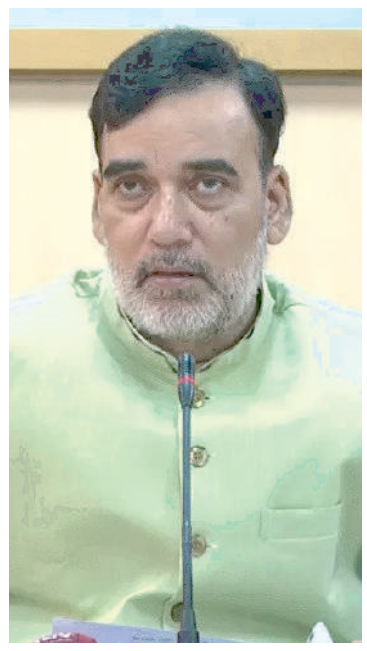

नई दिल्ली। सर्दियों में वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने विंटर एक्शन प्लान को लेकर शुक्रवार को पर्यावरण विभाग और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के साथ संयुक्त बैठक की। बैठक के बाद राय ने कहा कि 21 फोकस बिंदुओं पर आधारित विंटर एक्शन प्लान तैयार है। सभी विभागों ने निर्धारित फोकस बिंदुओं पर अलग-अलग रिपोर्ट सौंप दी है। इसी के अनुसार विंटर एक्शन प्लान तैयार किया गया है।

27 सितंबर होगी विंटर एक्शन प्लान की घोषणा

राय ने कहा कि 27 सितंबर को विंटर एक्शन प्लान की घोषणा की जाएगी। इस बार प्रदूषण कम करने को लेकर पहली बार 13 हॉटस्पॉट पर प्रदूषण की ड्रोन के जरिये निगरानी की जाएगी। साथ ही प्रदूषण की रोकथाम के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस वर्ष के विंटर एक्शन प्लान में हॉटस्पॉट, वाहन और धूल प्रदूषण, वर्क फ्रॉम होम, पराली और कूड़ा जलाना, औद्योगिक प्रदूषण, वाररूम व ग्रीन ऐप को उन्नत बनाना और केंद्र सरकार व पड़ोसी राज्यों से संवाद एवं इमरजेंसी उपाय के तौर पर ऑड-इवेन की तैयारी, कृत्रिम वर्षा फोकस बिंदु में शामिल हैं।

भाजपा अपने एलजी के जरिए दिल्ली में बिजली महंगी करने का षड्यंत्र जरूर रचेगी- आतिशी

सुषमा रानी

नई दिल्ली, भाजपा दिल्ली में बिजली की कीमतें बढ़ाना चाहती है। इस बाबत प्रेस वार्ता कर आम आदमी पार्टी की वरिष्ठ नेता एवं दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने कहा कि, उत्तर प्रदेश जैसी महंगी बिजली और लंबे पॉवर कट दिल्ली न देखने को मिले, इसके लिए अरविंद केजरीवाल को दोबारा मुख्यमंत्री बनाना ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों की 24 घंटे बिजली, सबसे सस्ती बिजली मिलती रहे। इसलिए अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना बहुत ज़रूरी है।

आतिशी ने कहा कि भाजपा का बिजली मॉडल, सबसे महंगी बिजली और लंबे-लंबे पॉवर कट का है। इस साल गर्मी में गुरुग्राम, नोएडा, ग्रेटर नोएडा और गाजियाबाद में 8-8 घंटे के पॉवर कट लगे। जबकि अरविंद केजरीवाल का मॉडल, देश में सबसे सस्ती और 24 घंटे बिजली देने का है। बीते जून महीने में दिल्ली ने 8400 मेगावाट की पीक डिमांड के बाद भी कहीं पर पावर कट नहीं हुआ।

उन्होंने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में बिजली की कीमतें दिल्ली से 4 गुना ज्यादा हैं। दिल्ली में 400 यूनिट बिजली का बिल 980 रुपए है जबकि भाजपा शासित मध्यप्रदेश में 3800 रुपए और महाराष्ट्र में 4460 रुपए है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपने एलजी के जरिए दिल्ली में भी बिजली महंगी करने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी, लेकिन हम दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे।

आतिशी ने कहा कि भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में बिजली कनेक्शन के दाम 250 फीसद बढ़ा दिए हैं। अब उत्तर प्रदेश में ग़रीब परिवार, गांव में रहने वाले परिवार, किसान परिवार जो 1 किलोवाट के छोटे-छोटे कनेक्शन लेते है, उसके लिए पहले मात्र 1200 रुपए देते थे, लेकिन अब भाजपा की सरकार ने उसे 250 फीसद बढ़ाकर 3000 रुपए कर दिया है। अब अगर किसी को 5 किलोवाट का कनेक्शन लेना है, जो कि एक आम मिडिल क्लास घरों के लिए सामान्य सी बात है, उसे भी भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार ने 118 फीसद बढ़ाकर 7967 रुपए से 17365 रुपए कर दिया है। यानी एक किलोवाट के कनेक्शन के लिए 250 फीसद और 5 किलोवाट के कनेक्शन के लिए 118 फीसद की वृद्धि की गई है।

आतिशी ने कहा कि यह वही उत्तर-प्रदेश की भाजपा की सरकार है, जिसने गर्मी में अपने बड़े शहरों नोएडा, ग्रेटर-नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद जैसे शहरों में 8-8 घंटे का पॉवर कट लगाया था। भाजपा के बिजली मॉडल में लंबे-लंबे पॉवर कट और सबसे महंगी बिजली मिलती है। इसलिए दिल्लीवालों के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो फिर से अरविंद केजरीवाल को लेकर आए और दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाए। वरना आज उत्तर प्रदेश जैसी महंगी बिजली और लंबे पॉवर कट दिल्ली में भी देखने को मिलेगी

उन्होने बताया कि मैं सभी दिल्लीवालों से कहना चाहती हूं कि जब फ़रवरी में चुनाव आयेगा, तब सबको मिलकर फिर से अरविंद केजरीवाल को अपना मुख्यमंत्री बनाना है। तभी दिल्ली में 24 घंटे और सबसे सस्ती बिजली मिलती रहेगी। आने वाले 4 महीनों में जबतक मेरे पास दिल्ली का मुख्यमंत्री होने की जिम्मेदारी है, मैं भी दिल्लीवालों की रक्षा करने का पूरा प्रयास करूंगी, क्योंकि मुझे पता है कि, आने वाले समय में भाजपा अपने एलजी के माध्यम से दिल्ली में बिजली महंगी करने के लिए कोई न कोई षड्यंत्र जरूर रचेगी। मैं आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की तरफ से यह वादा करती हूं कि हम दिल्ली में बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे।

' मैंने दिल से कहा' नया पॉडकास्ट लॉन्च करेंगे महेश भट्ट और पूजा भट्ट

सुषमा रानी

प्रसिद्ध फिल्म निर्माता महेश भट्ट और उनकी बेटी पूजा भट्ट इमरान जाहिद द्वारा निर्मित "मैंने दिल से कहा" नामक एक नया पॉडकास्ट लॉन्च करने के लिए तैयार हैं।

यह अनफ़िल्टर्ड और अंतरंग पॉडकास्ट प्रसिद्धि, प्रेम और लत जैसे विषयों का पता लगाएगा, जीवन की सबसे जटिल वास्तविकताओं पर एक गहरी और निडर नज़र डालेगा।

पॉडकास्ट श्रोताओं को अक्सर गलत समझी जाने वाली स्थिति पर एक कच्चा, आत्मनिरीक्षण करने का मौका देने का वादा करता है, जिसमें महेश भट्ट अपनी अंतर्दृष्टि साझा करते हैं कि कैसे बुरी आदत उन तरीकों से प्रकट होती है जिन्हें हम अनदेखा करते हैं।

व्यक्तिगत चिंतन और वर्षों के अवलोकन के माध्यम से, भट्ट श्रोताओं को यह चुनौती देने की उम्मीद करते हैं कि वे नशे की लत को जिस तरह से देखते हैं, उस पर पुनर्विचार करें, समाज से कलंक से आगे बढ़ने और सहानुभूति और समझ के साथ इसका सामना करने का आग्रह करें। भट्ट बताते हैं, ₹नशे की लत सिर्फ़ पदार्थों के बारे में नहीं है।₹ ₹यह एक कमी को पूरा करने के बारे में है, एक ज़रूरत जिसे लोग अक्सर पहचान नहीं पाते या चर्चा नहीं करते। ये व्यवहार पैटर्न ही हैं जो वास्तव में नशे की लत के मूल को परिभाषित करते हैं।₹

पूजा भट्ट भी अपने पिता के साथ पॉडकास्ट श्रृंखला में नजर आएंगी। पूजा ने बताया कि आगामी पॉडकास्ट नशे की लत के संवेदनशील और भावनात्मक पहलुओं का पता लगाएगा, इस विषय पर खुलकर चर्चा करेगा ।

"मैंने दिल से कहा₹ में स्पष्ट बातचीत, कच्ची अंतर्दृष्टि और पहले कभी नहीं बताई गई कहानियाँ होंगी जो इसके मेजबानों की कमज़ोरियों और ताकत को उजागर करती हैं। यह प्रसिद्धि से परे व्यक्तिगत यात्राओं को छूने का वादा करता है, उनके अनुभवों के भावनात्मक और दार्शनिक पहलुओं में

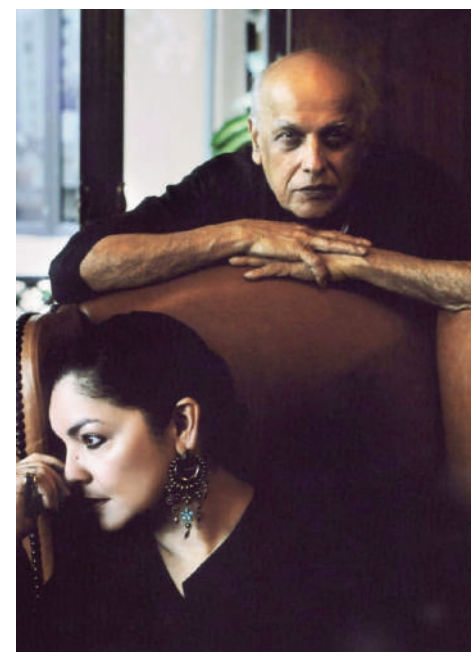

तल्लीन करता है। पॉडकास्ट महेश भट्ट की उल्लेखनीय विरासत और दर्शकों और उनके काम से प्रेरित लोगों के साथ उनके स्थायी बंधन का जश्न मनाने का प्रयास करेगा।

पॉडकास्ट का निर्माण महेश भट्ट के शिष्य इमरान जाहिद ने किया है। जाहिद कहते हैं, "यह प्रोजेक्ट मेरे दिल में एक खास जगह रखता है।₹ वह इस बात पर ज़ोर देते हैं कि महेश भट्ट और पूजा भट्ट उनके जीवन में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, और वह उनके साथ बिताए व्यक्तिगत और पेशेवर पलों को संजोते हैं।

यमुना की सफाई को लेकर किए जा रहे दावे खोखले, 37 में से 21 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट मानक पर खरे नहीं

दिल्ली में उत्पन्न लगभग 790 एमजीडी सीवेज में से लगभग 550-600 एमजीडी का उपचार एसटीपी में किया जाता है। उस उपचारित पानी में से लगभग 260 एमजीडी यमुना में चला जाता है जबकि 125 एमजीडी का उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है। बाकी का उपयोग जलाशयों को भरने और भूजल रिचार्ज करने के लिए किया जाता है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की नई रिपोर्ट आई है।

नई दिल्ली। यमुना की सफाई को लेकर किए जाने वाले बड़े-बड़े दावों के बीच दिल्ली में 37 सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) में से 21 अभी भी मानकों पर खरे नहीं उतर रहे हैं। जून-जुलाई के बाद अगस्त माह में भी दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) की रिपोर्ट इस सच्चाई को तथ्यात्मक रूप से बयां करती है।

डीपीसीसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि 37 एसटीपी का विश्लेषण मल कोलीफार्म, डिजोल्व ऑक्सीजन मांग, ठोस कचरा (टीएसएस), तेल, ग्रीस और उपचारित पानी में घुले फास्फेट के आधार पर किया गया था। इन मानकों पर 56 प्रतिशत एसटीपी विफल रहे।

बीओडी पानी की स्वयं को साफ करने की है क्षमता

गौरतलब है कि एसटीपी से उपचारित या अनुपचारित पानी आमतौर पर यमुना में चला जाता है। बहुत बार बागवानी के लिए उपयोग किया जाता है। बीओडी पानी की स्वयं को साफ करने की क्षमता को इंगित करता है क्योंकि यह पानी में कार्बनिक पदार्थों के उपचार के लिए आवश्यक आक्सीजन की मात्रा है। फिकल कोलीफॉर्म पानी में अनुपचारित सीवेज की उपस्थिति का बताता है।

रिपोर्ट के अनुसार, केशोपुर, निलोठी, नजफगढ़, पप्पन कलां, रोहिणी, नरेला, यमुना विहार, महरौली, वसंत कुंज, मोलडबंद, ओखला और घिटोरनी में एसटीपी मल कोलीफार्म के मापदंडों से मेल खाने में विफल रहे।

125 एमजीडी का होता है बागवानी के लिए उपयोग

एसटीपी से पानी नालों में जाता है और उनके माध्यम से नदी में मिल जाता है। दिल्ली में उत्पन्न लगभग 790 एमजीडी सीवेज में से लगभग 550-600 एमजीडी का उपचार एसटीपी में किया जाता है। उस उपचारित पानी में से, लगभग 260 एमजीडी यमुना में चला जाता है, जबकि 125 एमजीडी का उपयोग बागवानी के लिए किया जाता है। बाकी का उपयोग जलाशयों को भरने और भूजल रिचार्ज करने के लिए किया जाता है।

हालांकि जल बोर्ड सीवरेज उपचार के लिए अपनी स्थापित क्षमता को जनवरी में 632 एमजीडी से बढ़ाकर जुलाई में 712 एमजीडी करने में कामयाब रहा है, लेकिन कई सीवर या नालियां, ज्यादातर अनधिकृत कॉलोनियों में, अभी भी टैप नहीं की गई हैं।

अगस्त में बढ़ गया था प्रदूषण का स्तर

प्रमुख शहरी नालों की गुणवत्ता का आकलन करने के बारे में डीपीसीसी की एक अन्य रिपोर्ट में पाया गया कि अगस्त में, नदी में गिरने वाले कई बड़े नालों में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया था। नालों पर रिपोर्ट से पहले, यमुना पर डीपीसीसी के एक आकलन में वर्षा के बावजूद अगस्त में प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी की ओर इशारा किया गया था।

एसटीपी पर अगस्त के लिए डीपीसीसी के विश्लेषण पर जल बोर्ड के अधिकारियों से पक्ष भी मांगा गया, लेकिन मिला नहीं।

एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतने के खातिर भाजपा हर हथकंडे अपना रही- दुर्गेश पाठक

सुषमा रानी

नई दिल्ली। दिल्ली नगर निगम में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव जीतने के लिए भाजपा एक बार फिर आम आदमी पार्टी के पार्षदों को तोड़ने में जुट गई है। भाजपा में शामिल होने के लिए ''आप'' पार्षदों को लाखों-करोड़ रुपए का ऑफर दिया जा रहा है और भाजपा में शामिल नहीं होने पर ईडी-सीबीआई से परेशान करने की धमकी दी जा रही है। बुराड़ी से ''आप'' विधायक संजीव झा ने बताया कि भाजपा नेता सुंदर तंवर ने हमारे पार्षद को दो करोड़ रुपए और विधायक का टिकट देने का ऑफर दिया है। साथ ही, भाजपा में शामिल न होने पर ईडी-सीबीआई से परेशान करने की धमकी भी दी है। वहीं, बवाना से ''आप'' पार्षद रिंकू मुकेश सोलंकी के पति मुकेश सोलंकी ने बताया कि कुछ परिचित मुझे भी फोन कर स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भाजपा को वोट करने का दबाव बना रहे हैं। एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने कहा कि अब हमारे सभी पार्षद भाजपा का ऑफर लेकर आने वाले लोगों की रिकॉर्डिंग करेंगे और उसे जनता के बीच एक्सपोज करेंगे।

दिल्ली नगर निगम में ''आप'' के प्रभारी एवं विधायक दुर्गेश पाठक ने कहा कि एक तरफ देश मे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ईमानदार राजनीति चल रही है। जिसमें एक झूठा आरोप लगने अरविंद केजरीवाल ने कहा कि जब तक मैं जनता की अदालत में अग्नि परीक्षा पास नहीं कर लेता, तब तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठूंगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। पूरी दुनिया में ऐसा कोई एक उदाहरण नहीं होगा, जब मुख्यमंत्री के पद पर बैठा व्यक्ति कोई आरोप लगने पर इस्तीफा दिया हो। वहीं, दूसरी राजनीति भाजपा के नेतृत्व में चल रही है। इस राजनीति में झूठ, फरेब, बेइमानी, धोखाधड़ी, पार्टियों को तोड़ने और सांसद, विधायक और पार्षदों को खरीदने का काम चल रहा है।

दुर्गेश पाठक ने बवाना से ''आप'' के पार्षद रामचंद्र का उदाहरण देते हुए कहा कि भाजपा के लोगों ने उनको ईडी-सीबीआई की धमकी देकर

जबरदस्ती अपनी पार्टी में शामिल कराया। जब दो दिन बाद वह वापस आदमी पार्टी में लौट आए तो फिर भाजपा के लोगों ने उनको घर से उठा लिया। इसी तरह, पिछले कुछ दिनों से कई घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें भाजपा के लोग लगातार साम, दाम, दंड, भेद समेत हर हथकंडे अपना कर हमारे पार्षदों को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमने अपने सभी पार्षदों से कह दिया है कि कोई भी आपके पास आए तो उसकी सारी बात रिकॉर्ड कर लीजिए। क्योंकि इस भ्रष्टाचारी पार्टी का पर्दाफाश करना बहुत जरूरी है। भाजपा अपनी गंदी राजनीति छोड़ दे। जनता ने उन्हें हरा दिया तो अब वो भ्रष्टाचार से कमाए पैसे से हमारे पार्षदों को खरीदना चाहते हैं।

बुराड़ी से ''आप'' संजीव झा ने अपनी विधानसभा में भाजपा के लोगों द्वारा पार्टी के पार्षदों से संपर्क करने की घटना की जानकारी देते हुए कहा कि भाजपा एक गैंग है। इसका काम ही विधायकों की चोरी करना, पार्षदों को किडनैप करना और सत्ता के लिए किसी भी हद तक गिर जाना है। भाजपा पहले दिन से एमसीडी में जनता से ''आप'' को मिले जनाधार को खत्म करने और किसी भी तरह से सत्ता में बने रहने की साजिश कर रही है। अभी एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव है। मेरे विधानसभा में पार्टी के तीन पार्षद हैं। इसमें एक पार्षद के पास भाजपा से प्रत्याशी बने सुंदर तंवर गए। सुंदर तंवर ने उनको भाजपा में शामिल होने के बदले 2 करोड़ रुपए और विधायक का टिकट देने का ऑफर दिया। अगर भाजपा में शामिल नहीं होंगे तो ईडी-सीबीआई आपको परेशान करेगी। सुंदर तंवर ने यह भी कहा कि गोवा के मुख्यमंत्री भी आकर आपसे बात करना चाहते हैं। इसी तरह वह बाकी पार्षदों के पास भी जा रहे हैं और उनको डरा-धमका कर खरीदने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने कहा कि इतनी आसानी से भाजपा के लोग हमारे पार्षदों को तोड़ या खरीद नहीं सकते। अब कैमरे में रिकॉर्ड करके लोगों के बीच भाजपा को एक्सपोज करने की जरूरत है।

इस दौरान बवाना से ''आप'' पार्षद रिंकू मुकेश सोलंकी के पति मुकेश सोलंकी ने बताया कि गुरुवार को कुछ परिचितों का मेरे पास फोन आया और उन्होंने मिलने की बात कही। मुझे स्टैंडिंग कमेटी के चुनाव में भाजपा को वोट करने के लिए कहा गया। मैं 15 साल भाजपा में रहा हूं। जब गुरुवार को मुझ पर दबाव बनाया गया, तब अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को बताना पड़ा। हम ईमानदार आदमी है। हम न टूटेंगे और बिकेंगे। हम पूरी निष्ठा के साथ अरविंद केजरीवाल के साथ हैं और पार्टी के प्रति गद्दारी नहीं करेंगे।

गुरुग्राम के इस इलाके में रिहायशी घरों से काटे जाएंगे बिजली, पानी के साथ सीवर कनेक्शन; वजह आई सामने

परिवहन विशेष न्यूज

गुरुग्राम शहर के पालम विहार में 500 वर्ग गज के 11 रिहायशी प्लॉटों पर अब प्रशासन ने कार्रवाई का मन बना लिया है। यहां पर अवैध रूप से बने फ्लैटों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डीटीपीई की ओर से एक्शन शुरू हो गया है। आप इस खबर के माध्यम से जानिए किस-किस एरिया में यह कार्रवाई होगी।

गुरुग्राम। पालम विहार में 500 वर्ग गज के 11 रिहायशी प्लाटों पर अवैध रूप से बने 16-16 फ्लैटों पर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग के डीटीपीई की तरफ से कार्रवाई शुरू कर दी है। इस संबंध में डीटीपीई ने नगर निगम गुरुग्राम आयुक्त, कार्यकारी अभियंता को इन इमारतों के सीवर, पानी तथा ड्रेन का कनेक्शन काटने।

बिजली निगम को बिजली का कनेक्शन काटने तथा तहसीलदार को इन मकानों में आगे किसी भी प्रकार की रजिस्ट्री न करने को लेकर पत्र लिखा है। यह मामला पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में विचाराधीन है। पालम विहार सी-टू ब्लॉक रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन तथा स्थानीय निवासियों की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की हुई है।

अवैध निर्माण के कारण लोग हैं परेशान

पालम विहार के सी-टू ब्लॉक में अवैध निर्माण के चलते लोग परेशान हैं। दो सप्ताह पहले निवासियों की तरफ से बड़ा प्रदर्शन भी किया गया था। इसके बाद हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी गई, जिस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस जारी कर अगली सुनवाई तक जवाब दायर करने के निर्देश दिए हैं।

इसके बाद डीटीपीई कार्यालय भी मामले को पूरी तरह गंभीरता से ले रहा है। डीटीपीई की तरफ से प्लाट न0 913, 1310, 921, 1251, 924, 979बी, 956, 1226, 922, 935, 951 के विरुद्ध नगर निगम गुरुग्राम, बिजली निगम और तहसीलदार को पत्र लिखा गया है।

अवैध फ्लैटों के निर्माण के चलते स्थानीय लोगों को होती दिक्कत

इससे पहले भी डीटीपीई की तरफ से कई इमारत मालिकों के विरुद्ध एफआईआर भी दर्ज की हुई है। कुछ इमारत मालिकों ने अवैध तरीके से बिल्डिंग डी-सील कर ली है, जिसके बाद विभाग ने दोबारा सीलिंग की कार्रवाई करते हुए एक नई एफआईआर की भी सिफारिश की। अवैध फ्लैटों के निर्माण के चलते स्थानीय निवासी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर से बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।

हैरानी की बात यह है कि नियमों के हिसाब से एक फ्लोर पर ही एक ही यूनिट बन सकती है लेकिन बिल्डरों ने चार से छह यूनिट बना दी और तहसीलदारों की मिलीभगत से इनकी रजिस्ट्री भी करा दी गई है और उसी आधार पर बिजली कनेक्शन भी जारी हो गया।

इस प्रकार के अवैध निर्माण से यह शहर स्लम में तब्दील होता नजर आ रहा है। तीनों विभागों को कार्रवाई करने के संबंध में पत्र लिख दिया गया है। एन्फोर्समेंट कार्यालय अपनी तरफ से मामले में जो भी कार्रवाई है, उस पर अमल कर रहा है।

छापेमारी करने पहुंची बिजली विभाग की टीम को बनाया बंधक, फिर झुंड ने जमकर की पिटाई; ऐसे छुड़ाई जान

गाजियाबाद। बॉर्डर थाना क्षेत्र की मौलाना आजाद कॉलोनी में बृहस्पतिवार शाम को जांच अभियान के तहत छापेमारी करने गयी बिजली विभाग की टीम के साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। टीम द्वारा पुलिस कंट्रोल रूम को सूचना दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने टीम को मुक्त कराया। रिपोर्ट दर्ज कर पांच को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। बिजली विभाग के अवर अभियंता एवं उपखंड अधिकारी पंचम नवनीत पाण्डे विभाग की टीम के साथ बृहस्पतिवार शाम मौलाना आजाद कॉलोनी में बिजली की अवैध चोरी रोकने के लिए चेकिंग अभियान चला रही थी। अभियान के दौरान रति हॉस्पिटल के निकट एक निजी होटल में जांच के लिए जैसे ही पहुंचे, होटल संचालक शाहिद ने अपने सात-आठ साथियों के साथ चेकिंग रोकते हुए मारपीट करने लगे।

सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए और कमरे में बंद कर दिया

अधिकारियों ने बताया कि हमारे सरकारी दस्तावेज फाड़ दिए गए और हमें जबरन धक्का देकर एक कमरे में बंद कर दिया गया। इतना ही नहीं आरोपियों ने अभद्रता करते हुए जान से मारने की धमकी दी। किसी तरह 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। सहायक पुलिस आयुक्त अंकुर विहार भास्कर वर्मा ने बताया कि विद्युत निगम अधिकारियों की शिकायत पर एक नामजद 7-8 अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर पांच आरोपितों को हिरासत में लेकर मामले की जांच की जा रही है।

कैमरे में कैद हुआ खौफनाक मंजर, वीडियो देख कांपी हर किसी की रूह; तेज रफ्तार में एसयूवी कार से टकराई थी

गुरुग्राम में एक दिल दहला देने वाला हादसा हुआ है। हादसे के बाद खौफनाक मंजर एक्शन कैमरे में कैद हो गया। इस वीडियो को जिसने भी देखा उसकी रूह कांप गई। एक एसयूवी कार से बाइक सवार की टक्कर होने के बाद युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पुलिस ने वीडियो के आधार पर जांच शुरू कर दी है।

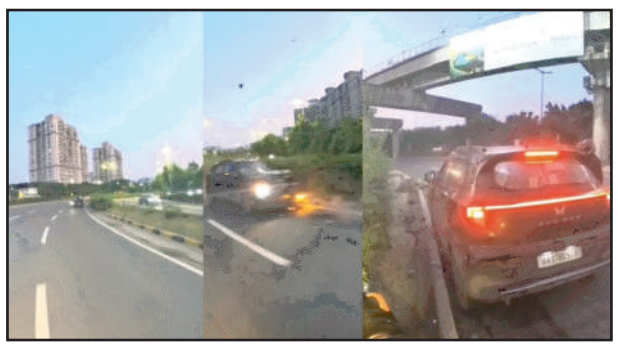

गुरुग्राम। गुरुग्राम में डीएलएफ फेस-2 मेट्रो स्टेशन के पास तेज रफ्तार से जा रही बाइक सामने से विपरीत दिशा से आई एक एक्सयूवी कार से टकरा गई। Accident Video इस हादसे में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। बताया गया कि घटना बीते रविवार की है।

गुरुवार को सामने आया वीडियो

वहीं, चार दिन बाद गुरुवार शाम को इस घटना का एक खौफनाक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी। यह वीडियो किसी सीसीटीवी फुटेज का नहीं बल्कि पीछे आ रही बाइक में लगे एक्शन कैमरे का है।

इस घटना में दिल्ली के द्वारका के बोचनपुर निवासी अक्षत गर्ग की मौत हो गई थी। उनके साथ पीछे आ रहे उनके दोस्त सेक्टर-23 कार्टरपुरी निवासी प्रद्युम्न ने बताया कि वह और उनके कुछ दोस्त डीएलएफ डाउन टाउन स्थित एक्सपीडिया ट्रैवलिंग कंपनी में काम करते हैं। अक्षत गर्ग भी साथ में काम करता था।

एक्शन कैमरे में कैद हुआ हादसा

बताया कि हर रविवार को वह सभी 6-7 दोस्त बाइक से एंबिएंस मॉल के पास इकट्ठे होकर मानेसर घाटी तक जाते थे। इस रविवार को भी वह सुबह पांच बजे मानेसर जाने वाले थे। सबसे पहले अक्षत और प्रद्युम्न आ गए। सभी दोस्त आ जाएं, इससे पहले वे बाइक में पेट्रोल भराने के लिए साइबर सिटी की तरफ जा रहे थ। प्रद्युम्न की बाइक में एक्शन कैमरा लगा हुआ था।

उनका कहना है कि जब भी वह इस तरह की ट्रिप पर जाते थे तब वह एक्शन कैमरा बाइक के हैंडल लगा लेते थे। कैमरा बाइक या हेलमेट में कहीं भी एक स्क्रू के सहारे फिट हो सकता है और यात्रा की रिकॉर्डिंग करता है। उस सुबह भी उन्होंने एक्शन कैमरा बाइक के हैंडल में फिट किया था।

बताया गया कि बाइक से जाने के दौरान एक्शन कैमरे ने इस सड़क हादसे का खौफनाक वीडियो रिकॉर्ड किया। जिसमें दिख रहा है कि अक्षत अपनी पल्सर 220 सीसी बाइक से आगे 70 की स्पीड से चल रहे थे। डीएलएफ मेट्रो स्टेशन के पास सामने से महिंद्रा एक्सयूवी गाड़ी आती है और तेज रफ्तार में अक्षत की बाइक कार से भिड़ जाती है।

मृतक के दोस्त ने बताया कि एक्शन कैमरे की कीमत 50 हजार रुपये है। यह पॉकेट साइज का होता है और आसानी से कहीं भी फिट हो जाता है।

भूखंडों का आवंटन कर सकता है निरस्त यमुना प्राधिकरण, मिलेगा आखिरी मौका; नियमों में हुआ बदलाव

यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क में आवंटित 26 भूखंडों का आवंटन निरस्त कर सकता है। यह भूखंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली कंपनियों को आवंटित किए गए थे। प्राधिकरण ने आवंटियों को प्रोजेक्ट बदलने के लिए नोटिस जारी किया था लेकिन आवंटियों ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। प्राधिकरण आखिरी मौका देते हुए नोटिस जारी करेगा। प्रोजेक्ट में बदलाव न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

परिवहन विशेष न्यूज

ग्रेटर नोएडा। यमुना प्राधिकरण मेडिकल डिवाइस पार्क में आवंटित 26 भूखंडों का आवंटन निरस्त कर सकता है। 26 सितंबर को बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। यह भूखंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली कंपनियों को आवंटित किए गए थे।

प्राधिकरण ने आवंटियों को प्रोटेक्ट बदलने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन आवंटियों ने अभी तक कोई पहल नहीं की है। प्राधिकरण आखिरी मौका देते हुए नोटिस जारी करेगा। प्रोजेक्ट में बदलाव न करने पर आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

मेडिकल डिवाइस पार्क में 74 भूखंडों का आवंटन किया

यमुना प्राधिकरण ने सेक्टर 28 में साढ़े तीन सौ एकड़ में विकसित हो रहे मेडिकल डिवाइस पार्क में 74 भूखंडों का आवंटन किया है। कोविड के दौरान ऑक्सीजन की जरूरत को देखते हुए 26 भूखंड ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बनाने वाली कंपनियों को इकाईयों लगाने के लिए दिए गए थे, लेकिन कोविड के बाद अब हालात बदल चुके हैं।

इस कारण प्राधिकरण ने नोटिस जारी करते हुए आवंटियों से कहा था कि वह ऑक्सीजन कंसंट्रेटर की बजाए दूसरा चिकित्सा उपकरण से संबंधित दूसरे प्रोजेक्ट लगाए। लेकिन 26 आवंटियों ने प्राधिकरण के नोटिस को बाद कोई पहल नहीं की। इकाई लगाने के बजाए भूखंडों की खरीद फरोख्त हो रही है।

प्राधिकरण ने आवंटियों को अंतिम मौका देने का फैसला किया है। मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुणवीर सिंह का कहना है कि बोर्ड बैठक में इसका प्रस्ताव रखा जाएगा। अगर आवंटी प्रोजेक्ट में बदलाव नहीं करते हैं तो आवंटन निरस्त कर दिया जाएगा।

भूखंड आवंटन नीति में बदलाव

मेडिकल डिवाइस पार्क में भूखंड आवंटन नीति में भी बदलाव कर दिया गया है। लॉटरी के बजाए भूखंडों का आवंटन साक्षात्कार के माध्यम से होगा।

प्राधिकरण की मेडिकल डिवाइस पार्क योजना में 27 भूखंड के सापेक्ष 47 आवेदन मिले हैं। इन आवेदन की जांच फार्मा विभाग की तकनीकी समिति करेगी। इससे पहले मेडिकल डिवाइस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के कार्यकारी निदेशक की अध्यक्षता में गठित समिति आवेदनों की जांच करेगी। केंद्रीय समिति की जांच में सभी मिले आवेदकों का साक्षात्कार कर भूखंड आवंटन होगा। मेडिकल डिवाइस प्रमोशन काउंसिल की संरचना तैयार करने के लिए भी कार्रवाई शुरू हो गई है।

हरियाणा चुनाव में कांग्रेस के 'फ्री' ऑफर से क्या मिलेगी सत्ता की चाबी?

कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई आकर्षक वादे पेश किए हैं। इनमें से प्रमुख वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है, जो सीधे अरविंद केजरीवाल के मॉडल से प्रेरित है।

भारतीय राजनीति में मुफ्त योजनाओं का चलन पिछले कुछ वर्षों में तेजी से बढ़ा है, और यह एक ऐसी रणनीति बन गई है जिसे राजनीतिक दल अपने चुनावी अभियानों में बड़ी चतुराई से इस्तेमाल कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का मुफ्त पानी और बिजली देने का मॉडल हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मुफ्त राशन देने का कार्यक्रम, ये सभी नीतियां राजनीतिक सफलता की कुंजी बन चुकी हैं। पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी से लेकर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन तक, सभी ने इन योजनाओं का उपयोग करके अपनी सत्ता को मजबूत किया है। अब हरियाणा में कांग्रेस ने इसी परंपरा को अपनाते हुए अपने चुनावी अभियान में एक नया मोड़ लिया है, जिससे वह पिछले दस वर्षों से सत्ता से बाहर रहने की स्थिति को बदलने का प्रयास कर रही है।

कांग्रेस ने हाल ही में हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए अपने घोषणा पत्र में कई आकर्षक वादे पेश किए हैं। इनमें से प्रमुख वादा 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का है, जो सीधे अरविंद केजरीवाल के मॉडल से प्रेरित है। यह एक स्पष्ट संकेत है कि कांग्रेस ने समझ लिया है कि लोगों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली योजनाएं ही उनकी राजनीतिक जीत की कुंजी हो सकती हैं। कांग्रेस के नेता इस बार अपने वादों में आत्मविश्वास से भरे नजर आ रहे हैं, और उन्होंने इन योजनाओं को लुभावना बनाने की हर संभव कोशिश की है।

इसे भी पढ़ें: हरियाणा के चुनावी मुद्दों से मिल रहे हैं सत्ता-विरोधी संकेत

महिलाओं के प्रति कांग्रेस का यह नया दृष्टिकोण भी ध्यान देने योग्य है। पार्टी ने 18 वर्ष से ऊपर की प्रत्येक महिला को प्रतिमाह 2000 रुपये देने का वादा किया है। यह योजना मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना से प्रेरित है, जिसने उस राज्य में चुनावी परिणामों को पलटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कांग्रेस का यह वादा महिलाओं को सीधे आर्थिक सहायता देकर उन्हें अपने पक्ष में करने की एक रणनीति है। इसके अतिरिक्त, बुजुर्गों, दिव्यांगों और विधवाओं को भी छह हजार रुपये की पेंशन देने का प्रस्ताव रखा गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है।

किसानों को आकर्षित करने के लिए कांग्रेस ने एमएसपी (न्यूनतम समर्थन मूल्य) को कानूनी गारंटी देने का वादा किया है। यह घोषणा किसानों के हित में महत्वपूर्ण मानी जा रही है, और इससे यह स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने ग्रामीण समुदाय की चिंताओं को समझा है। भारतीय राजनीति में किसानों का एक अहम स्थान है, और उनकी समस्याओं को सुलझाने का प्रयास करना हमेशा से राजनीतिक दलों के लिए फायदेमंद रहा है। इसके अलावा, कांग्रेस ने किसानों को तुरंत मुआवजे का आश्वासन देकर उनकी समस्याओं को तेजी से हल करने का भी वादा किया है।

कांग्रेस ने तेलंगाना के मॉडल को भी अपनाने की कोशिश की है, जिसमें गैस सिलेंडर के लिए मात्र 500 रुपये देने का प्रस्ताव है। यह योजना गरीब परिवारों के लिए महत्वपूर्ण है, और इसके तहत 100 गज के मुफ्त प्लॉट और पक्के मकान देने का भी वादा किया गया है। यह आवास की समस्या को हल करने में मदद करेगा और नागरिकों को एक स्थायी घर प्रदान करेगा।

कांग्रेस ने राजस्थान की चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल किया है। इसके तहत गरीबों के लिए 25 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने का वादा किया गया है। स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता पर हाल के वर्षों में सवाल उठते रहे हैं, और यह योजना कांग्रेस के लिए एक महत्वपूर्ण दांव साबित हो सकती है। हालांकि राजस्थान में यह योजना अपेक्षित सफलता नहीं प्राप्त कर पाई थी, लेकिन हरियाणा में इसकी लोकप्रियता को लेकर सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं।

कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करने का भी भरोसा दिया है, जो सरकारी कर्मचारियों की एक बड़ी मांग है। इस योजना से न केवल कर्मचारियों को, बल्कि उनके परिवारों को भी फायदा होगा, और इससे कांग्रेस का समर्थन बढ़ सकता है। चुनावी प्रचार में कांग्रेस ने अपनी योजनाओं को प्रभावशाली तरीके से पेश किया है, जो दर्शाता है कि वह अपने मतदाताओं को खुश करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है।

हालांकि, कांग्रेस के इन दावों की सफलता केवल चुनाव के नतीजों पर निर्भर करेगी। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि मुफ्त योजनाएं हमेशा कारगर नहीं होतीं। कई बार मतदाता इन योजनाओं के साथ-साथ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों को भी ध्यान में रखते हैं। भ्रष्टाचार, प्रशासनिक विफलता और कानून-व्यवस्था की स्थिति जैसे मुद्दे भी मतदाताओं के फैसले को प्रभावित करते हैं।

इस प्रकार, हरियाणा में कांग्रेस ने चुनावी मैदान में उतरते हुए एक महत्वपूर्ण रणनीति अपनाई है। अब देखना यह है कि क्या ये मुफ्त योजनाएं वास्तव में उन्हें सत्ता में वापस लाने में मदद कर पाएंगी या नहीं। भाजपा और अन्य दलों की प्रतिक्रियाएं भी इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। अंततः, हरियाणा का चुनाव यह साबित करने के लिए एक बड़ा मंच होगा कि मुफ्त योजनाएं कितनी प्रभावी हैं और क्या वे एक राजनीतिक दल की किस्मत को बदलने में सक्षम हैं।

कांग्रेस की यह कोशिश एक संकेत है कि चुनावी राजनीति में सामाजिक कल्याण की योजनाएं अब एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं, और यह देखा जाना बाकी है कि क्या ये योजनाएं हरियाणा में कांग्रेस के लिए राजनीतिक सफलता की चाबी बन पाएंगी।

फरीदाबाद में 30 मेडिकल स्टोर मालिकों को मिला नोटिस, हो सकता है लाइसेंस निलंबित

फरीदाबाद। जिले के 30 मेडिकल स्टोर संचालकों को अनियमितताएं पाए जाने पर नोटिस दिया गया है। जवाब देने के लिए स्टोर संचालक को 15 दिन का समय दिया गया है। संतोषजनक जवाब न देने पर दवा स्टोर का लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है।

जिला औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने यह कार्रवाई की है। विभाग की ओर से पिछले 15 दिनों में जब मेडिकल स्टोर का निरीक्षण किया गया तो किसी मेडिकल स्टोर पर फार्मासिस्ट नहीं था।

खरीद और बिकी का नहीं था पूरा रिकॉर्ड

कई जगह टीम को स्टोर संचालक मौके पर उपलब्ध दवा की खरीद और बिकी का पूरा रिकॉर्ड नहीं दिखा पाए। बिक्री के लिए रखी दवाओं के साथ ऐसी दवाएं भी मिलीं, जिनकी वैधता खत्म हो चुकी है। जबकि नियमानुसार ऐसी दवाएं अलग रखी जानी चाहिए।

जिले में लगभग तीन हजार मेडिकल स्टोर

बता दें कि जिले में लगभग तीन हजार मेडिकल स्टोर हैं। विभाग की टीम की ओर से महीने भर में 250 से अधिक दवा स्टोर का निरीक्षण किया जाता है। कमियां पाई जाने पर नोटिस भेजे जाते हैं।

वरिष्ठ औषधि नियंत्रण अधिकारी करण गोदारा ने बताया कि मेडिकल स्टोर संचालक को अपना पक्ष रखने को अवसर दिया जाता है। अगर अनियमिताओं संबंधी नोटिस का समय पर जवाब नहीं मिलता तो आगे कार्रवाई की जाती है।

– :सौजन्य :–
ईवी ड्राइव द फ्यूचर

20 मिनट में चार्ज हो जाएगी ये ईवी कार , अब भारत में भी होगी उपलब्ध

परिवहन विशेष न्यूज

दक्षिण कोरियाई कार निर्माता कंपनी किआ मोटर्स किफायती दामों पर हाई क्लास कारें पेश करती है। कंपनी ने अब भारत में एक नई ईवी कार लॉन्च करने की योजना बनाई है। बताया जा रहा है कि कंपनी इस कार को 3 अक्टूबर को पेश करेगी।

किआ ईवी9 में हाई पावर 99.8 kWh बैटरी पैक होगा। यह कमाल की कार एक बार फुल चार्ज होने पर 500km तक की रेंज देगी। कार फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, इसलिए यह सिर्फ 20 मिनट में चार्ज हो जाएगी। कंपनी ने नई किआ ईवी9 में हाई क्लास सेफ्टी फीचर्स दिए हैं। इसमें लेन कीप असिस्ट और इमरजेंसी ब्रेकिंग की सुविधा दी गई है।

यह कार एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) के साथ आती है, जो सड़क हादसों को नियंत्रित करने में मदद करती है। कार में एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम और अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर्स मिलते हैं। इस दमदार कार में 6 एयरबैग और बड़ी सनरूफ जैसे फीचर्स दिए गए हैं। कार में ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन दिया गया है।

किआ ईवी9 में हाई पावर के लिए 2 इलेक्ट्रिक मोटर दिए गए हैं, जो सड़क पर 384 PS की पावर और 700 Nm का टॉर्क जनरेट करते हैं। फिलहाल कंपनी ने इस कार की कीमत का खुलासा नहीं किया है। अनुमान है कि यह कार बीएमडबल्यूiX और मर्सिडीज़-बेंज EQE एसयूवी को टक्कर देगी और इसकी कीमत 80 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी जा सकती है। कार में अलॉय व्हील दिए गए हैं।

हुंडई और स्कोडा के बीच हाइड्रोजन सहयोग पर समझौता ज्ञापन

परिवहन विशेष न्यूज

हुंडई मोटर कंपनी और स्कोडा समूह ने हाइड्रोजन मोबिलिटी समाधान और ऊर्जा-कुशल नवाचारों पर सहयोग करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राग में कोरिया-चेक बिजनेस समिट के दौरान घोषित यह साझेदारी हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी, पर्यावरण-अनुकूल गतिशीलता को आगे बढ़ाने और एक स्थायी भविष्य में योगदान देने पर केंद्रित है। समझौते की मुख्य विशेषताओं में हुंडई की हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों को अपनाना और गतिशीलता से परे हाइड्रोजन ऊर्जा के लिए व्यापक बाजार अवसरों की खोज करना शामिल है।

मुख्य बातें:

साझेदारी का लक्ष्यः हाइड्रोजन अपनाने में तेजी लाना और कार्बन तटस्थता में योगदान देना।

फोकस क्षेत्रः हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रणालियों को अपनाना, ऊर्जा-कुशल समाधान, और हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तार करना।

हस्ताक्षरकर्ताः हुंडई मोटर कंपनी के कार्यकारी उपाध्यक्ष केन रामिरेज़ और स्कोडा समूह के सीईओ पेट्र नोवोत्नी।

लक्षित बाज़ारः चेक गणराज्य और वैश्विक क्षेत्र जहां स्कोडा समूह काम करता है।

हाइड्रोजन पारिस्थितिकी तंत्र का विस्तारः हुंडई अपनी हाइड्रोजन ईंधन सेल प्रौद्योगिकी को साझा करेगी और दोनों पक्ष गतिशीलता से परे अवसरों की खोज करेंगे, जिसका लक्ष्य व्यापक औद्योगिक अनुप्रयोगों तक पहुंचना होगा।

हुंडई और स्कोडा का सहयोग हाइड्रोजन प्रौद्योगिकियों के माध्यम से एक स्थायी गतिशीलता पारिस्थितिकी तंत्र बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जैसा कि दोनों कंपनियां भविष्य की ओर देखती हैं, वे हुंडई की ईंधन सेल विशेषज्ञता और स्कोडा की गतिशीलता परियोजनाओं का लाभ उठाने के लिए मिलकर काम करेंगी।

हुंडई के कार्यकारी उपाध्यक्ष केन रामिरेज़ ने कहा, ₹स्कोडा समूह के साथ हमारी साझेदारी का उद्देश्य हाइड्रोजन अपनाने में तेजी लाना है, जो चेक गणराज्य सहित वैश्विक बाजारों में हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी और कार्बन तटस्थता के विकास में योगदान देगा।"

स्कोडा समूह के सीईओ पेट्र नोवोत्नी ने कहा, ₹हमारा मानना है कि ऊर्जा-कुशल समाधानों के साथ-साथ हाइड्रोजन, अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए गतिशीलता को बदलने में एक आवश्यक भूमिका निभाएगा।"

हाइड्रोजन प्रौद्योगिकी में हुंडई का नेतृत्व इसके HTWO ब्रांड के माध्यम से अच्छी तरह से स्थापित है , जो हाइड्रोजन मूल्य श्रृंखला के सभी पहलुओं को कवर करता है। यह सहयोग स्कोडा समूह को अपने गतिशीलता उत्पादों और परियोजनाओं में उपयोग के लिए हुंडई की उन्नत प्रणालियों को अपनाने की अनुमति देता है, जिसका उद्देश्य कार्बन फुटप्रिंट को कम करना और टिकाऊ परिवहन समाधान बनाना है।

इसके अलावा, चेक गणराज्य के नोसोविस में हुंडई का विनिर्माण संयंत्र इस क्षेत्र के प्रति कंपनी की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 350,000 वाहनों की वार्षिक क्षमता के साथ, यह यूरोप में सबसे आधुनिक सुविधाओं में से एक है और चेक गणराज्य में सबसे बड़ा विदेशी निवेश है।

इस समझौते के माध्यम से, हुंडई और स्कोडा समूह नए व्यावसायिक अवसरों की खोज करेंगे, विभिन्न क्षेत्रों में पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन समाधान लाएंगे, जिसका उद्देश्य गतिशीलता में बदलाव लाना और वैश्विक स्तर पर स्वच्छ ऊर्जा के भविष्य में योगदान करना है।

देश की पहली इलेक्ट्रिक सुपरबाइक अल्ट्रावॉयलेटी F99 हुई पेश, 3 सेकंड में पकड़ेगी 100 kmph की स्पीड

परिवहन विशेष न्यूज

अल्ट्रावायलेट ऑटोमोटिव में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक सुपरबाइक को पेश किया है। यह बाइक Ultraviolette F99 है। इस बाइक की टॉप स्पीड 265 किमी प्रति घंटे होगी जो महज 3 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ लेगी। इतना ही नही कंपनी दावा कर रही है कि आने वाले कुछ महीनों में अल्ट्रावायलेट F99 सुपरबाइक कई रिकॉर्ड बनाएगी।

नई दिल्ली। अल्ट्रावॉयलेट ऑटोमोटिव ने भारत में F99 इलेक्ट्रिक सुपरबाइक को पेश किया है। यह इलेक्ट्रिक सुपरबाइक बड़ी मोटर और हाई स्पीड के साथ आती है। इस बाइक को पेश करने को लेकर कंपनी का कहना है कि F99 का लक्ष्य भारतीय मोटरसाइकिल के लिए सबसे तेज़ क्वार्टर मील और सबसे ज़्यादा टॉप स्पीड का नया रिकॉर्ड बनाना है। आइए जानते हैं कि यह किन फीचर्स के साथ आती है।

भारत की पहली इलेक्ट्रिक सुपरबाइक

Ultraviolette F99 इलेक्ट्रिक सुपरबाइक को पहली बार EICMA 2023 में 120 Hp के मोटर के साथ अपने कॉन्सेप्ट फॉर्म में पेश की गई थी। उस समय इस बाइक की टॉप स्पीड 265 किमी प्रति घंटे दावा की गई थी। वहीं, यह बाइक 3 सेकंड में 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड पकड़ने में सक्षम है। वर्तमान कंपनी ब्रांड प्रोडक्शन वेरिएंट के आंकड़ों के बारे में चुप है, लेकिन उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है कि अगले 90 दिनों में Ultraviolette F99 इलेक्ट्रिक सुपरबाइक कई रिकॉर्ड बनाएगी। जिसमें से एक किसी भारतीय मोटरसाइकिल के लिए सबसे अधिक गति प्राप्त करना और दूसरा कि यह भारत की पहली इलेक्ट्रिक सुपरबाइक होगी।

Ultraviolette F99 के स्पेसिफिकेशन्स

Ultraviolette F99 इलेक्ट्रिक सुपरबाइक के टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की बात करें तो इसका व्हीलबेस 1400 mm है। इसकी हाइट 1050 mm, फ्रंट और रियर में 17 इंच का व्हील दिया गया है। इसकी बॉडी में कार्बन फाइबर दिया गया है। बाइक का वजन 178 किलोग्राम है। Ultraviolette F99 इलेक्ट्रिक बाइक देखने में पूरी तरह से रेसिंग बाइक है।

ईवी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के लिए जल्द आएंगे नए नियम, अब शर्तों पर मिलेगी सब्सिडी

परिवहन विशेष न्यूज

सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए स्थानीयकरण नियमों को और सख्त बनाने पर विचार कर रही है। इसके लिए इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग से बातचीत भी शुरू हो गई है। ईवी कंपनियों को देश में निर्मित इलेक्ट्रिक वाहनों में इस्तेमाल होने वाले अधिक पार्ट्स का स्थानीयकरण करना होगा। प्रधानमंत्री ई-ड्राइव योजना के तहत सरकारी सब्सिडी प्राप्त करने के लिए कंपनियों को इन नए स्थानीयकरण नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। फेम 2 नीति में ईवी के लिए 18 कंपोनेंट के आयात की अनुमति थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसे घटाकर 12 किया जा सकता है।

करीब 6 ऐसे पार्ट्स होंगे जिन्हें फिलहाल आयात करने की अनुमति है लेकिन आने वाले दिनों में इन पार्ट्स को घरेलू बाजार से खरीदना होगा। इसका उद्देश्य भारत में स्थानीय स्तर पर पार्ट्स का उत्पादन बढ़ाना है ताकि देश में इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग को बढ़ावा दिया जा सके।

भारी उद्योग सचिव कामरान रिजवी ने कहा, "हमें भारत के इलेक्ट्रिक वाहन उद्योग की क्षमता पर पूरा भरोसा है। इसलिए हम चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम में कुछ बदलाव कर सकते हैं।"

हालांकि, सेमीकंडक्टर और बैटरी जैसे महत्वपूर्ण घटकों को इन नए नियमों से बाहर रखा जा सकता है, यानी उन्हें आयात करने की अनुमति होगी। यह फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि इन घटकों का स्थानीय उत्पादन अभी पूरी तरह से संभव नहीं है। साथ ही कंपनियों को इन नियमों को लागू करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा ताकि वे अपने काम को नए प्रावधानों के अनुसार ढाल सकें। इस कदम का मुख्य उद्देश्य भारत को इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में आत्मनिर्भर बनाना और विदेशों से आयात पर निर्भरता कम करना है।

पंजाब में बढ़ी ईवी वाहनों की खरीद

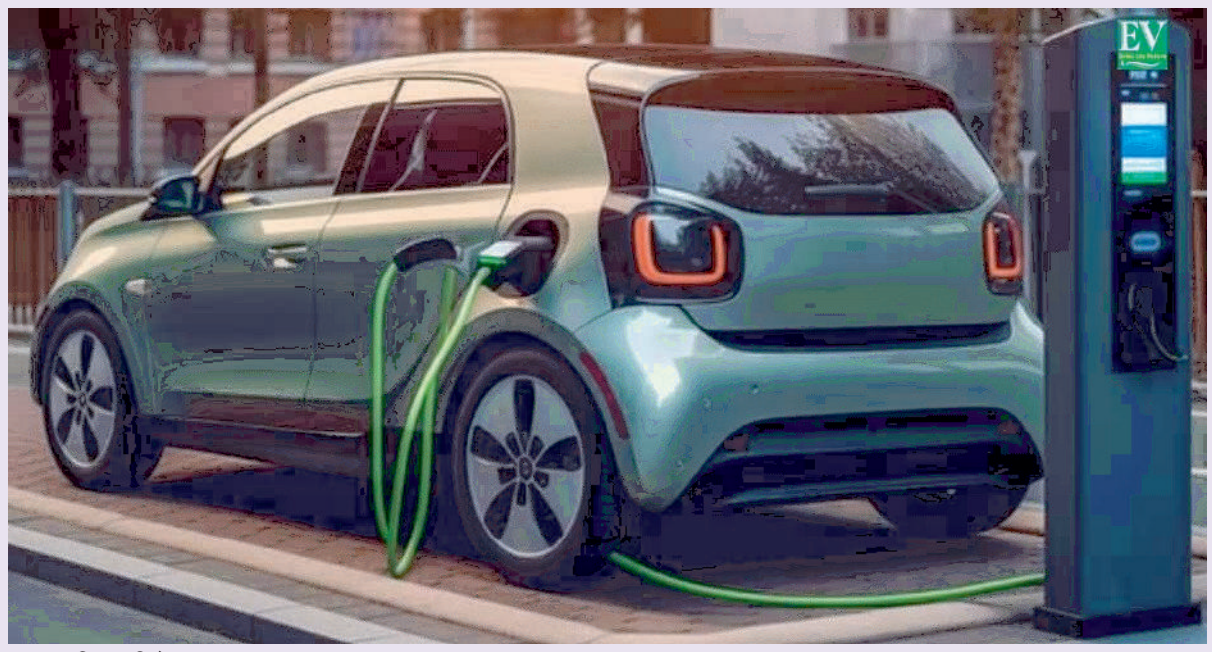

परिवहन विशेष न्यूज

पंजाब सरकार ने 21 फरवरी, 2023 को प्रदेश की ईवी नीति लॉन्च की थी। ईवी नीति आने के बाद से राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में तेजी आई है। पिछले तीन सालों में 2024 तक राज्य में ईवी वाहनों की खरीद में 17 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

पिछले साल 2023 में कुल 25,743 इलेक्ट्रिक और 13,667 हाइब्रिड वाहन खरीदे गए थे। इस साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद 26,014 तक पहुंच गई है, जबकि नवरात्रि, रामनवमी, अक्षय तृतीया, दीपावली और नए साल के त्योहारी सीजन के दौरान ईवी वाहनों की खरीद का यह आंकड़ा इस बार 35 हजार के पार जाने की उम्मीद है।

पंजाब परिवहन विभाग के अनुसार पिछले दो से ढाई साल में राज्य में ट्रांसपोर्ट वाहनों की खरीद में बढ़ोतरी हुई है, खासकर डीजल से चलने वाले वाहनों की। इनमें बस, टेंपो ट्रैवलर, ट्रांसपोर्ट वाहन और अन्य डीजल वाहन शामिल हैं। वर्ष 2021 में डीजल वाहनों की संख्या 77150 है, 2022 में यह 80963, 2023 में 89410 और 2024 में अब तक 71862 वाहन सड़कों पर आ चुके हैं। आने वाले दिनों में कमर्शियल वाहनों की खरीद में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि पंजाब सरकार ने हाल ही में कैबिनेट मीटिंग में टूरिस्ट वाहनों पर परमिट फीस कम कर दी है।

लुधियाना को उत्तर भारत का औद्योगिक हब बनाने के उद्देश्य से पंजाब सरकार धनानसू गांव में 378.77 एकड़ क्षेत्र में हाईटेक वैली विकसित कर रही है। इस वैली को पंजाब लघु उद्योग एवं निर्यात निगम द्वारा विकसित किया जा रहा है। 378.77 एकड़ भूमि के पूरे क्षेत्र के लिए नक्शा, योजना, भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू), ईआईए अधिसूचना के तहत पर्यावरण मंजूरी, रेरा आदि की मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। इस परियोजना पर 365 करोड़ रुपये खर्च होंगे।

2025 से भारत से बाहर के देशों की सड़कों पर दौड़ेंगे इस कंपनी के इलेक्ट्रिक स्कूटर

परिवहन विशेष न्यूज

हीरो मोटोकॉर्प ने देश के बाहर भी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर बेचने की तैयारी कर ली है। कंपनी 2025 के मध्य तक यूके, फ्रांस और स्पेन में अपने विडा इलेक्ट्रिक ब्रांड के तहत ई-स्कूटर लॉन्च करने की तैयारी में है। यूके और यूरोपीय बाजारों में कंपनी का यह पहला उद्यम है, जहां इसका लक्ष्य इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग को पूरा करना है। कंपनी का यह कदम भारत-यूके मुक्त व्यापार समझौते पर चल रही चर्चा के साथ मेल खाता है। इससे ऑटोमोटिव उद्योग में टैरिफ कम हो सकते हैं, जिससे विकास के कई अवसर भी पैदा होंगे।

फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार हीरो मोटोकॉर्प के मुख्य कार्यकारी निरंजन गुप्ता ने इन क्षेत्रों में अपने ई-स्कूटर के प्रति सकारात्मक उपभोक्ता भावना को उजागर किया। कंपनी जो पहले से ही एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका में एक प्रमुख खिलाड़ी है, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में बदलाव के रूप में इस उत्साह का लाभ उठाने की योजना बना रही है। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन सेगमेंट में कंपनी को ज्यादा सफलता नहीं मिली है।

अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर योजनाओं के अलावा, हीरो अपने प्रीमियम मावरिक मॉडल सहित पारंपरिक पेट्रोल इंजन वाली बड़ी मोटरसाइकिलों को यूके और अन्य यूरोपीय देशों में निर्यात करने की संभावना तलाश रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि इन विकसित बाजारों में सफलता के लिए अधिक महंगी और प्रीमियम मोटरसाइकिलों की पेशकश करने की आवश्यकता होगी। हार्ले-डेविडसन के साथ हीरो की मौजूदा साझेदारी उसे भारतीय बाजार के लिए प्रतिष्ठित ब्रांड की मोटरसाइकिलों का उत्पादन करने की अनुमति देती है।

कंपनी का यूरोप में प्रवेश ऐसे समय में हो रहा है जब 2020 में अपडेट किए गए भारत के वाहन उत्सर्जन मानक अब वैश्विक नियमों के अनुरूप हैं, जो भारतीय उत्पादकों के लिए नए दरवाजे खोल रहा है। हीरो मोटोकॉर्प जैसे भारतीय निर्माता चीनी आयात पर अधिक शुल्क के कारण विकसित बाजारों में नए अवसरों की तलाश कर रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प ने अगस्त 2024 में 512,360 इकाइयाँ बेचीं। यह महीने-दर-महीने आधार पर 38% की वृद्धि है। पिछले साल की तुलना में कंपनी ने साल-दर-साल बिक्री में 8% की वृद्धि हासिल की।

कला, मनोरंजन और मीडिया में करियर के अवसर

विजय गर्ग

कला, मनोरंजन और मीडिया के बारे में जानकारी नहीं, बल्कि कल्पना और नवीनता ही बुद्धिमत्ता के वास्तविक संकेतक हैं। यदि आपमें अपने सपनों को साकार करने की क्षमता है तो कला, मनोरंजन और मीडिया आपके लिए उपयुक्त करियर विकल्प है। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए लोगों में असाधारण रचनात्मक प्रतिभा और आविष्कारशीलता होनी चाहिए। इंजीनियरिंग, चिकित्सा और सिविल इंजीनियरिंग में उच्च स्तर की प्रतिस्पर्धा के कारण, व्यक्ति (विशेषकर युवा पीढ़ी) नए विषयों और व्यवसायों की तलाश में हैं। स्कूली शिक्षा के अलावा, कला, मनोरंजन और मीडिया उद्योग भी है, जिसने रचनात्मक, कल्पनाशील और प्रतिभाशाली युवाओं के लिए रोजगार की संभावनाओं का यथासंभव विस्तार और सुधार किया है। यह परस्पर जुड़ा हुआ क्षेत्र किसी की क्षमता का पता लगाता है और उसे पेशेवर सीढ़ी पर चढ़ने की अनुमति देता है। कला, मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र किसी भी नौकरी उद्योग की सबसे अधिक अंतर-विषयक बातचीत की मांग कर सकते हैं क्योंकि इस क्षेत्र में रोजगार मुख्य रूप से परियोजना-आधारित है, जिसमें कैरियर की सफलता के लिए स्वायत्त कार्य और अन्योन्याश्रित प्रबंधन क्षमताओं दोनों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, नई प्रौद्योगिकियां लगातार कई कला कार्य पथों की सीमाओं और कौशल सेटों को बदल रही हैं। परिणामस्वरूप, मौलिक कला-क्षेत्र के रोजगार को कलात्मक रचनात्मकता, रूपक प्रतिनिधित्व, प्रतीकात्मक संबंधों और तकनीकी क्षमताओं के लगातार बदलते मिश्रण की आवश्यकता होती है। सफल कैरियर की तैयारी में व्यापक और गहन शैक्षणिक और तकनीकी तैयारी के साथ-साथ 21वीं सदी की कौशल संपत्तियों जैसे अनुकूलनशीलता, समस्या-समाधान क्षमताओं और पारस्परिक कौशल का विकास शामिल है। डिज़ाइन, दृश्य और मीडिया कला; कला प्रदर्शन; उत्पादन और प्रबंधकीय कला; और गेम डिज़ाइन और इंटीग्रेशन कला, मीडिया और मनोरंजन उद्योग में चार प्रमुख कैरियर मार्ग हैं। मीडिया, कला और मनोरंजन उद्योग अक्सर परियोजना-आधारित होते हैं, विचारों और रचनात्मक उत्पादों को आगे बढ़ाने के लिए कई उद्योगों के पेशेवरों के साथ अच्छे संपर्क की आवश्यकता होती है। कला रोजगार में रचनात्मकता, रचनात्मक चित्रण और तकनीकी क्षमताओं के विभिन्न घटकों की आवश्यकता होती है। कक्षा के बाहर का व्यावहारिक अनुभव आपको रचनात्मक क्षेत्र में करियर बनाने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में मदद कर सकता है। ऐसी नौकरी चुनना बेहतर है जो आपकी रुचियों, प्रतिभाओं और विश्वासों से मेल खाती हो। कला, मीडिया और मनोरंजन उद्योग क्षेत्र में काम बनाने, परिष्कृत करने और साझा करने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान की खोज से टीम वर्क, संचार, रचनात्मक सोच और निर्णय लेने की क्षमताओं को बढ़ावा मिलता है-प्रतिस्पर्धी और मीडिया-समृद्ध क्षेत्र में सफलतापूर्वक कार्य करने के लिए आवश्यक गुण इक्कीसवीं सदी। कला क्या है? कला मानवीय गतिविधियों की एक विविध श्रृंखला है जिसमें कलाकार की कल्पना, वैचारिक विचारों या तकनीकी क्षमताओं को व्यक्त करने वाले दृश्य, श्रवण, या कलाकृतियों (कलाकृतियों) का निर्माण, साथ ही कला का उत्पादन, कला आलोचना, कला इतिहास अनुसंधान शामिल है। और कला का कलात्मक प्रसार। कला, अपनी सबसे मौलिक परिभाषा में, भावनाओं, विचारों और टिप्पणियों को संप्रेषित करने के लिए संचार की एक विधि के रूप में परिभाषित की जा सकती है। मनोरंजन क्या है? जो कुछ भी आपको आनंदित और आरामदायक बनाता है उसे मनोरंजन माना जा सकता है। यह एक प्रकार का पोर्टल है जो आपको आपके दैनिक जीवन में आनंद, आनंद और आनंद प्रदान करता है। नाटकों और फिल्मों का प्रदर्शन, साथ ही पढ़ना, नृत्य, गाना और टेलीविजन देखना जैसे शौक, मनोरंजन के उदाहरण हैं. चूँकि हम मनोरंजन युग में रहते हैं, ऐसे प्रतिभाशाली और मनोरंजक लोगों की आवश्यकता बढ़ रही है। कुशल नई पीढ़ी इस क्षेत्र में एक खुशहाल करियर बना सकती है और फिल्म संपादन, निर्देशन, निर्माण, कार्टूनिस्ट, टीवी एंकर, वृत्तचित्र फिल्म निर्माता, साउंड इंजीनियर, पटकथा लेखक, बाजार अनुसंधान विश्लेषक, आवाज जैसे विविध क्षेत्रों में काम करके अपना सपना हासिल कर सकती है। कलाकार, वीडियो संपादक, मीडिया नियोजक, सामग्री लेखक, विपणन शोधकर्ता, कॉपी राइटिंग, सिनेमैटोग्राफर इत्यादि। मीडिया क्या है? आज के परिवेश में, मीडिया दुनिया भर में होने वाली असंख्य घटनाओं के बारे में सभी को सूचित रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मीडिया संचार चैनलों या उपकरणों का एक संग्रह है जिसका उपयोग सूचनाओं को संग्रहीत करने और संप्रेषित करने के लिए किया जाता है। मीडिया का जनमत तैयार करने और समाज के विकास पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। इसमें टीवी और रेडियो के माध्यम से प्रसारण, दृश्य-श्रव्य फिल्मों और वीडियो के माध्यम से मनोरंजन और इंटरनेट जैसे उप-प्रपत्र शामिल हैं, जिसमें ब्लॉग, फ़ोरम, संगीत और समाचार शामिल हैं। अब, किताबें, पत्रिकाएँ और पत्र-पत्रिकाएँ प्रकाशित करने के अलावा, विदेशी डाक मेल, टेलीफोन और नया मीडिया भी उपलब्ध है। इस प्रकार, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों में करियर की संभावनाएं असीमित हैं। कला, मनोरंजन और मीडिया उद्योग में संभावित नौकरी शीर्षकों के कुछ उदाहरण हैः अभिनेता कला निर्देशक कला शिक्षक ग्राफ़िक डिज़ाइनर औद्योगिक डिजाइनर संग्रहालय क्यूरेटर मल्टीमीडिया कलाकार और एनिमेटर प्रवेश स्तर के करियर (हाई स्कूल डिप्लोमा के साथ) अभिनेता उद्घोषक प्रसारण तकनीशियन कैमरा तकनीशियन डिस्क या वीडियो जॉकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण संचालक प्रकाश तकनीशियन नमूना मेकअप कलाकार फोटोग्राफर सहायक रंगमंच का मज़दूर करतब करने वाला व्यक्ति ध्वनि तकनीशियन विजुअल आर्टिस्ट वॉइस-ओवर कलाकार तकनीकी स्तर के करियर (एए-कला में एसोसिएट या एएस-विज्ञान में एसोसिएट डिग्री या प्रमाणपत्र के साथ) कैमरा संचालक फ़िल्म निर्माता ग्राफ़िक डिज़ाइनर/ग्राफ़िक कलाकार मुख्य उत्पादन पकड़ संगीत मंत्री नकारात्मक कटर प्रोप निर्माता फोटोग्राफर फोटो पत्रकार रिकॉर्डिंग स्टूडियो सहायक रेडियो/टेलीविज़न प्रसारक पटकथा लेखक मंच प्रबंधक विशेष प्रभाव समन्वयक वेब डिजाइनर व्यावसायिक स्तर के करियर (बीएस या बीए डिग्री के साथ) वास्तुकार स्तंभकार कोरियोग्राफर विदेशी भाषा दुभाषिया औद्योगिक डिजाइनर संगीत शिक्षक संगीत संगतकार संगीत निर्देशक/कंडक्टर चिकित्सा वैज्ञानिक चित्रकार मीडिया और डिज़ाइन कला प्रशिक्षक निर्माता प्रकाशक साउंड इंजीनियर/साउंड डिज़ाइन संपादक तकनीकी लेखक दृश्य प्रभाव समन्वयक कला, मनोरंजन और मीडिया के लिए पात्रता मानदंड कला, मनोरंजन और मीडिया में करियर बहुत रोमांचक और मनोरंजक हो सकता है। चूंकि ये क्षेत्र हमारी इच्छाओं और इच्छाओं को पूरा करने वाले हैं। ये बहु-विषयक डोमेन हैं जो रचनात्मक और काल्पनिक प्रतिभाओं को आकर्षक कैरियर मार्ग प्रदान कर सकते हैं। कला के लिएः भारत में ऐसे कई प्रतिभाशाली और रचनात्मक लोग हैं, जिनके पास विचारों और विचारों को वास्तविकता में बदलने का कौशल है, लेकिन उनकी प्रतिभा सभी के लिए गुमनाम है। किसी की क्षमता और प्रतिभा का पता लगाने के लिए, कला को एक विषय के रूप में सीखना आवश्यक है और इसके लिए निम्नलिखित मानदंडों को बनाए रखा जाना चाहिएः उम्मीदवारों को सीबीएसई बोर्ड या किसी राज्य बोर्ड या समकक्ष से 10+2 स्तर उत्तीर्ण होना चाहिए। छात्रों के लिए न्यूनतम 50% कुल अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। छात्रों को हायर सेकेंडरी स्कूल में अंग्रेजी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़नी चाहिए। मनोरंजन के लिएः टीमनोरंजन जगत में प्रवेश के लिए उम्मीदवारों को किसी भी स्ट्रीम से इंटरमीडिएट उत्तीर्ण होना चाहिए या परीक्षा देने वाले छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। चुनिंदा सीमित सीटों के साथ मनोरंजन अकादमी में प्रवेश दूसरों की तरह प्रतिस्पर्धी है। इच्छुक उम्मीदवारों को प्रवेश प्रदान करने के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित की जाती है। इस प्रकार, केवल मजबूत रचनात्मक क्षमता और प्रतिभा वाले छात्र ही उस सीट के पात्र हैं। मीडिया के लिएः जो उम्मीदवार मीडिया पाठ्यक्रम करने के इच्छुक हैं, उन्हें निम्नलिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करना होगाः उम्मीदवारों को किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक बोर्ड से किसी भी स्ट्रीम में 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। उम्मीदवारों को 12वीं कक्षा में कम से कम 55% का न्यूनतम कुल अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। उसी के लिए, आरक्षित उम्मीदवारों के लिए योग्यता प्रतिशत 12वीं स्तर में कुल अंकों का 50% है। जो उम्मीदवार अपने 12वीं बोर्ड परीक्षा स्कोरकार्ड की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वे अनंतिम आधार पर भी आवेदन कर सकते हैं। कैरियर मार्ग 1. डिज़ाइन, विजुअल और मीडिया आर्ट्स पाथवे यह क्षेत्र ऐसे व्यवसायों को कवर करता है जो मुख्य रूप से दृश्य कला, डिजिटल मीडिया और वेब-आधारित टूल और संसाधनों के माध्यम से खुद को संचार और अभिव्यक्त करते हैं। इस कैरियर पथ के लिए दृश्य कला अवधारणाओं और नई और उभरती डिजिटल प्रक्रियाओं दोनों में ज्ञान और कौशल के विकास की आवश्यकता होती है जो व्यक्तियों को वर्तमान कार्यस्थल अभ्यास की समझ के अलावा, व्यवसायों और व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला में जटिल अवधारणाओं को बनाने और संचार करने में सक्षम बनाती है। करियर/करियर क्षेत्रः कलात्मक निर्देशक वाणिज्यिक कलाकार डिजिटल एनिमेटर संग्रहालय क्यूरेटर वेब डिजाइनर 2. प्रदर्शन कला मार्ग परफॉर्मिंग आर्ट्स पाथवे में ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जिनमें व्यक्तिगत कलाकार किसी द्वितीयक भौतिक माध्यम के बजाय सीधे कला और मनोरंजन का निर्माण करते हैं। प्रदर्शन करने वाले कलाकार वे साधन हैं जिनके माध्यम से रचनात्मक अभिव्यक्ति व्यक्त की जाती है। करियर/करियर क्षेत्रः अभिनेता (जैसे, स्टेज, फ़िल्म, वीडियो, डीवीडी), प्रदर्शन करने वाला कलाकार संगीतकार, म्यूजिक अरेंजर, कंडक्टर गायक, नर्तक, संगीतकार वॉयसओवर कलाकार, कथावाचक 3. प्रोडक्शंस और प्रबंधकीय कला मार्ग रचनात्मक अभिव्यक्ति के किसी भी रूप या माध्यम का उपयोग किया जाता है, कला, मीडिया और मनोरंजन उद्योग के सभी व्यवसायों में ₹प्रकाशन₹ या किसी न किसी रूप में सार्वजनिक प्रदर्शन शामिल होता है। परिणामस्वरूप, उत्पादन और प्रशासनिक कला ट्रैक सामान्य दर्शकों को कला, मीडिया और मनोरंजन प्रदान करने के लिए आवश्यक तकनीकी क्षमताओं और संगठनात्मक और प्रबंधकीय समझ दोनों पर जोर देता है। करियर/करियर क्षेत्रः घटना योजनाकार थिएटर, टेलीविजन, संगीत कार्यक्रम और मोशन पिक्चर के निर्माता/निर्देशक ध्वनि डिज़ाइन संपादक स्टेज मैनेजर/प्रोडक्शन मैनेजर प्रतिभा प्रबंधन नाट्य एवं प्रसारण तकनीशियन दृश्य प्रभाव समन्वयक 4. गेम डिज़ाइन और एकीकरण मार्ग जो छात्र गेम डिज़ाइन और इंटीग्रेशन ट्रैक को आगे बढ़ाते हैं, वे गेम डिज़ाइन उद्योग के साथ-साथ निकटवर्ती तकनीकी व्यवसायों में अवसरों के लिए तैयार होते हैं। छात्रों को गेम डिज़ाइन, एनीमेशन, ग्राफिक्स और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की ठोस समझ मिलेगी। वे गणित, भौतिकी, अंग्रेजी भाषा कला, सामाजिक विज्ञान और उद्यमिता के अपने ज्ञान का उपयोग करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि छात्र रचनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, संचार, सहयोग और तकनीकी दक्षता जैसे 21वीं सदी के कौशल विकसित करेंगे, जो पूरे नौकरी बाजार में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा देगा। गेम डिज़ाइन और इंटीग्रेशन पाथवे में छात्र हैंअत्यधिक प्रतिस्पर्धी गेम डिज़ाइन उद्योग में प्रगति के लिए आवश्यक प्रवेश स्तर की नौकरियों और आगे की माध्यमिक शिक्षा दोनों के लिए तैयार। वे गेम परीक्षक/विश्लेषक, 2-डी और 3-डी एनिमेटर, स्टोरीबोर्ड, स्तरीय कलाकार, बनावट कलाकार, सिनेमाई कलाकार, गेम डिजाइनर, गेम प्रोग्रामर और प्रोडक्शन टीम मैनेजर बनने के लिए प्रशिक्षण लेते हैं। इस पाठ्यक्रम को पूरा करने वाले छात्रों को वीडियो गेम डिज़ाइन में रचनात्मक भागीदार बनने के लिए आवश्यक कौशल और ज्ञान प्राप्त होता है, साथ ही रचनात्मक उद्योग के सभी क्षेत्रों में काम करने की क्षमता भी मिलती है। करियर/करियर क्षेत्रः 2-डी/3-डी एनिमेटर कंप्यूटर गेम डिज़ाइनर/डेवलपर इलेक्ट्रॉनिक सिमुलेशन सलाहकार खेल परीक्षक कला, मनोरंजन और मीडिया उद्योग में वेतन संभावनाएं विभिन्न क्षेत्रों में रोज़गार की असंख्य संभावनाओं की तरह, ऐसी क्षमताओं का पारिश्रमिक अगणनीय है। यदि वे किसी फर्म में काम करते हैं, तो वे रुपये के बीच कमाई की उम्मीद कर सकते हैं। 30,000 और रु. पहले 38,000 प्रति माह (लगभग)। इन विशेषज्ञों का वेतन पैकेज उनकी रचनात्मक और कल्पनाशील क्षमता से परिभाषित होता है। उस समय मान्यता प्राप्त फर्मों में, एक अनुभवी और योग्य विशेषज्ञ 7-8 लाख (लगभग) से लेकर सीमा से परे तक पर्याप्त वेतन पैकेज अर्जित कर सकता था। प्रतिष्ठित कंपनियाँ अन्य चीज़ों के अलावा आकर्षक बोनस, प्रोत्साहन, छुट्टियाँ और कंपनी पार्टियाँ भी प्रदान करती हैं। जो लोग कलाकार बनते हैं और टीवी या फिल्म उद्योगों में काम करते हैं, वे विभिन्न प्रकार के अतिरिक्त लाभों के साथ-साथ लाखों में अविश्वसनीय मासिक वेतन कमा सकते हैं।

राय

गणेशोत्सव का उद्घोष

त्योहार के मूड में परिवेश की संगत और बाजार के रुख में आ रहे बदलाव ने, हिमाचल की पहचान बदल दी। ताजातरीन उदाहरण गणेशोत्सव का है जहां न कोई सरकार और न ही कोई ओहदा शिरकत कर रहा है, बल्कि तमाम सांस्कृतिक समारोहों से ऊपर इसका सामाजिक उद्गार हो गया। गणेशोत्सव के मार्फत एक लघु भारत का उदय हिमाचल के शहर से गांव तक सफर करता रहा और जहां महिला मंडल इसकी पृष्ठभूमि में विविध सांस्कृतिक पहलुओं का मंचन करते देखे गए। यह दीगर है कि इस बहाने समाज का संगठित स्वरूप विकसित हुआ, लेकिन गणेश चतुर्थी से विसर्जन तक के सांस्कृतिक सफर में राज्य और प्रशासन की भूमिका में और सक्रियता, तैयारी, हस्तक्षेप तथा जिम्मेदारी की आवश्यकता है। राज्य के कला-संस्कृति विभाग को अपने सांस्कृतिक कैलेंडर में सामुदायिक त्योहारों की सूची बढ़ाते हुए गणेशोत्सव, छठ पूजा व क्रिसमस जैसे उत्सवों के बढ़ते हुए प्रचलन को अंगीकार करना होगा। छठ पूजा का महत्त्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश से आकर बसा जन समुदाय है, जो हिमाचल में आकर अपने आर्थिक सपनों के साथ अपनी संस्कृति का परिचय करवा रहा है। गणेशोत्सव सामुदायिक उल्लास का अनुशासित फलक है, जहां सांस्कृतिक नियमावली महाराष्ट्र से यहां पहुंच कर एक व्यापक संदेश, परिवर्तन व सामाजिक भूमिका का समर्थन कर रही है। यह त्योहार सबसे लंबा तथा विशुद्ध रूप से समाज को सांस्कृतिक उजास दे रहा है, तो इसका मूल्यांकन कई तरह से होना चाहिए। मसलन गणेशोत्सव अपने साथ कला के महत्त्व से बाजार खड़ा कर रहा है। हजारों मूर्तियों का उद्योग, महज कुछ दिनों में यहां की अर्थ व्यवस्था से धन निर्यात कर देता है, क्योंकि मूर्तिकार बाहर से आ रहे हैं।

कहने को हमने कुछ कालेजों में आर्ट विषय व म्यूजियम में चित्रकला सीखने के स्कूल खोल दिए, लेकिन गणेशोत्सव की आर्थिकी में स्थानीय मूर्तिकार को तैयार नहीं कर पाए। क्रिसमस जैसे त्योहार ने हिमाचल की बेकरी व गिफ्ट बाजार की रौनक को नया अंदाज सौंप दिया। जाहिर है हर त्योहार के सांस्कृतिक व धार्मिक पक्ष के साथ बाजार का स्वभाव बदल जाता। बहरहाल गणेशोत्सव के दस दिन हिमाचल के बदलते परिदृश्य की कहानी भी हैं, जहां जीवन को अब इस तरह का मनोरंजन भी चाहिए और विसर्जन के हर पहलू को देखें, तो कितने ही मेले खड्डों-नालों और नदियों में डुबकी लगाने का शृंगार कर रहे हैं। क्या प्रशासन को यह खबर होती है कि गणेशोत्सव की टुकड़ियां कितनी बढ़ गईं और किस खड्ड की ओर बढ़ कर विसर्जन करेंगे। चामुंडा में एक युवा विसर्जन करते बाल-बाल बचा, लेकिन नादौन के दो युवकों का डूबना विसर्जन पद्धति पर सवालिया निशान पैदा करता है। ऐसे में हमें विसर्जन की सुरक्षा में स्थल तय करके ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जो 'घाट पर्यटन' को सशक्त करे।

कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप महत्वपूर्ण हैं

कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं जो क्षमता, आत्मविश्वास और अनुकूलनशीलता का निर्माण करता है। ये कार्यक्रम व्यावहारिक, नौकरी-विशिष्ट शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना आज के तेजी से बदलते नौकरी बाजार में, प्रभावी कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप तेजी से महत्वपूर्ण हो गए हैं। दोनों औपचारिक शिक्षा और वास्तविक दुनिया के कार्य अनुभव के बीच महत्वपूर्ण पुल प्रदान करते हैं, जो व्यक्तियों को उद्योग सेटिंग्स में अपने कौशल का सम्मान करते हुए उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए तैयार करते हैं। ये कार्यक्रम विकास को सशक्त बनाते हैं, क्षमताओं को परिष्कृत करते हैं और भविष्य की सफलता के लिए रास्ते बनाते हैं, जिसका अकेले पारंपरिक शिक्षा में अक्सर अभाव होता है। भारत दुनिया के सबसे युवा देशों में से एक है, इसकी 54 प्रतिशत से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है और 62 प्रतिशत से अधिक कामकाजी आयु वर्ग (15-59 वर्ष) में है। देश वर्तमान में अच्छी तरह से प्रशिक्षित, कुशल श्रमिकों की भारी कमी से जूझ रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) की एक रिपोर्ट के अनुसार, अनुमानित रूप से केवल 2.3 प्रतिशत भारतीय कार्यबल ने औपचारिक कौशल प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जबकि यूके में 68 प्रतिशत, जर्मनी में 75 प्रतिशत, संयुक्त राज्य अमेरिका में 52 प्रतिशत और जापान में 80 प्रतिशत. आधुनिक शिक्षण संस्थान कौशल भारत मिशन में महत्वपूर्ण रहे हैं, जो व्यावहारिक, व्यावहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने और उद्योग-प्रासंगिक प्रशिक्षण प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं। मौजूदा नौकरी बाजार की मांगों के अनुरूप अपने पाठ्यक्रम को अद्यतन रखने के लिए विभिन्न उद्योगों के साथ साझेदारी में, ये संस्थान छात्रों को इंटर्नशिप, प्रशिक्षुता और लाइव परियोजनाओं के माध्यम से वास्तविक दुनिया का अनुभव प्राप्त करने में मदद करते हैं। इसके परिणामस्वरूप व्यावहारिक कौशल, उद्योग अनुभव और वास्तविक दुनिया की चुनौतियों से निपटने की तैयारी के साथ अत्यधिक मांग वाली प्रतिभाओं का निर्माण होता है। इंटर्नशिप बनाम अप्रेंटिसशिप इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप, हालांकि कुछ मायनों में समान हैं, कार्य-आधारित शिक्षा में अलग-अलग उद्देश्यों की पूर्ति करते हैं। इंटर्नशिप अक्सर छोटी होती है, आमतौर पर कुछ महीनों तक चलती है, और उन्हें भुगतान या अवैतनिक किया जा सकता है। वे छात्रों या हाल ही में स्नातक हुए लोगों को पेशेवर सेटिंग में अनुभव प्राप्त करने, वास्तविक परियोजनाओं पर काम करने और किसी विशेष उद्योग की गतिशीलता को समझने का अवसर प्रदान करते हैं। किसी छात्र के व्यावहारिक कौशल को बढ़ाने के लिए इंटर्नशिप आमतौर पर अकादमिक अध्ययन के समानांतर या स्नातक होने के तुरंत बाद की जाती है। दूसरी ओर, प्रशिक्षुता अधिक संरचित और दीर्घकालिक होती है। वे आम तौर पर कुशल व्यवसायों या तकनीकी क्षेत्रों में नौकरी के प्रशिक्षण के साथ कक्षा निर्देश को जोड़ते हैं, और औपचारिक योग्यता या प्रमाणन की ओर ले जाते हैं। प्रशिक्षु वजीफा अर्जित करते हैं क्योंकि वे सीखते हैं और अनुभवी पेशेवरों के साथ मिलकर काम करते हैं जो उन्हें उनके चुने हुए पेशे के लिए आवश्यक विशिष्ट कौशल प्राप्त करने में मार्गदर्शन करते हैं। इसके अलावा, डिग्री प्रशिक्षुता कौशल विकास, उद्योग सहयोग और व्यापक शिक्षा को बढ़ावा देने, एनईपी 2020 के दृष्टिकोण के साथ सहजता से संरेखित होती है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप की प्रासंगिकता कौशल विकास के लिए इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे व्यावहारिक अनुभव प्रदान करते हैं जो क्षमता, आत्मविश्वास और अनुकूलनशीलता का निर्माण करता है। ये कार्यक्रम व्यावहारिक, नौकरी-विशिष्ट सीखने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जैसे सॉफ्टवेयर में महारत हासिल करना या संचार और टीम वर्क कौशल विकसित करना। हाई स्कूल और कॉलेज के 94 प्रतिशत छात्रों का मानना है कि इंटर्नशिप या अप्रेंटिसशिप में भाग लेना पहले महत्वपूर्ण है।पूर्णकालिक नौकरी सुरक्षित करना। इसके अतिरिक्त, 74 प्रतिशत पारंपरिक चार-वर्षीय शैक्षणिक पथ के बजाय इंटर्नशिप जैसे अवसरों को आगे बढ़ाने को प्राथमिकता देते हैं। प्रशिक्षु अक्सर विश्लेषणात्मक सोच और समस्या-समाधान की आवश्यकता वाली परियोजनाओं पर काम करते हैं, जबकि प्रशिक्षु किसी शिल्प को बेहतर बनाने के लिए विशेष प्रशिक्षण से गुजरते हैं। नेटवर्किंग के अवसर एक और लाभ हैं, क्योंकि वे व्यक्तियों को पेशेवर नेटवर्क बनाने की अनुमति देते हैं, जिससे भविष्य में नौकरी के अवसर और उद्योग संबंधी अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। इंटर्नशिप और अप्रेंटिसशिप करियर अन्वेषण और परिवर्तन के अवसर भी प्रदान करते हैं, जिससे करियर परिवर्तन आसान हो जाता है। अंत में, वे तेजी से प्रतिस्पर्धी नौकरी बाजार में रोजगार और प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करते हैं, क्योंकि नियोक्ता शैक्षणिक योग्यता के अलावा व्यावहारिक अनुभव वाले उम्मीदवारों की तलाश करते हैं। प्रशिक्षुता का श्रेय और उसका प्रभाव यूजीसी का नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (एनसीआरएफ) इंटर्नशिप और औद्योगिक परियोजनाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम संरचना में अनुभवात्मक शिक्षा को शामिल करने की अनुमति देता है। इस घटक को ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) कहा जाता है। ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग (ओजेटी) के रूप में प्रशिक्षुता का यह श्रेय कौशल विकास में अनुभवात्मक शिक्षा को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। छात्रों को व्यावहारिक उद्योग अनुभव के लिए अकादमिक क्रेडिट अर्जित करने की अनुमति देकर, एनसीआरएफ सैद्धांतिक ज्ञान और वास्तविक दुनिया के अनुप्रयोग के बीच अंतर को कम करता है। 1 क्रेडिट के लिए प्रासंगिक अनुभव और अर्जित दक्षता/पेशेवर स्तरों सहित 40 से 45 घंटे की अनुभवात्मक शिक्षा। फ़ील्ड दौरे, औद्योगिक दौरे आदि जैसी गतिविधियाँ भी सीखी गई अवधारणाओं के अवलोकन और/या अनुप्रयोग के रूप में महत्व रखती हैं। आम तौर पर, एक अकादमिक क्रेडिट लगभग 15-16 घंटे की प्रत्यक्ष या सैद्धांतिक शिक्षा से मेल खाता है, इसलिए 45 घंटे इस राशि के बराबर सीखने का प्रदर्शन करना चाहिए। शिक्षार्थियों को अपने सीखने को प्रतिबिंबित करने के लिए अपने सभी अनुभवों को अपनी शैक्षणिक लॉगबुक में दर्ज करना आवश्यक है। यह प्रतिबिंब उनकी अनुभवात्मक शिक्षा को अकादमिक क्रेडिट मानदंडों के साथ संरेखित करने में मदद करता है। मूल्यांकन और मूल्यांकन लर्निंग आउटकम मैपिंग पर आधारित है और इसलिए, अनुभवात्मक सीखने के परिणामों को प्राप्त क्रेडिट के साथ मैप किया जाता है। इन सीखने के परिणामों को पाठ्यक्रम के सैद्धांतिक शिक्षण घटकों के साथ तालमेल और पूरक होना चाहिए। यह एकीकरण न केवल समग्र शिक्षा को बढ़ावा देता है बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि प्रशिक्षुता को शैक्षिक उपलब्धि के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में मान्यता दी जाए। प्रशिक्षुता कार्यक्रम मजबूत उद्योग-अकादमिक सहयोग को बढ़ावा देते हैं, क्योंकि वे कार्यबल की कमी को दूर करते हुए छात्रों को उद्योग-प्रासंगिक कौशल से लैस करते हैं। अप्रेंटिसशिप एंबेडेड डिग्री प्रोग्राम (एईडीपी), कौशल विकास में एक अभिनव दृष्टिकोण, अकादमिक शिक्षा को नौकरी पर प्रशिक्षण के साथ जोड़ता है। एईडीपी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह छात्रों को एक समृद्ध, व्यावहारिक सीखने का अनुभव प्रदान करता है, जो उन्हें उद्योग की मांगों को पूरा करते हुए तत्काल रोजगार के लिए तैयार करता है। यह एक कुशल कार्यबल के निर्माण के लिए इंटर्नशिप और प्रशिक्षुता को महत्वपूर्ण बनाता है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि छात्र न केवल अकादमिक रूप से मजबूत हैं बल्कि पेशेवर रूप से भी सक्षम हैं। सरकार समर्थित इंटर्नशिप के माध्यम से कैरियर की संभावनाओं को बढ़ाना जुलाई 2024 के बजट में भारत के प्रशिक्षुता कार्यक्रम को बढ़ाने के उद्देश्य से कई पहल की गई हैं। भारत सरकार एक व्यापक इंटर्नशिप कार्यक्रम के माध्यम से देश के युवाओं के बीच कौशल विकास को सक्रिय रूप से बढ़ावा दे रही है, जिसका उद्देश्य देश भर में मूल्यवान अवसर प्रदान करना है।500 कंपनियाँ। यह पहल 5,000 रुपये का मासिक इंटर्नशिप वजीफा और 6,000 रुपये का एकमुश्त भत्ता प्रदान करती है। भाग लेने वाली कंपनियां इन राशियों का दावा करने के लिए अपने कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) फंड का उपयोग कर सकती हैं, जिससे कुशल पेशेवरों की अगली पीढ़ी के पोषण में उद्योग की भागीदारी को बढ़ावा मिलेगा। उद्योग की भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से, केंद्र ने प्रदर्शन-आधारित अनुदान, कर छूट और प्रशिक्षण लागत प्रतिपूर्ति के माध्यम से नियोक्ता प्रोत्साहन बढ़ाया है। यह प्रासंगिक प्रशिक्षण सुनिश्चित करने और प्रशिक्षुता कार्यक्रमों की क्षमता बढ़ाने के लिए एक गुणवत्ता आश्वासन संगठन स्थापित करने के लिए उद्योग निकायों के साथ सहयोग भी बढ़ा रहा है। आईटी, नवीकरणीय ऊर्जा और उन्नत विनिर्माण जैसे बढ़ते उद्योगों में प्रशिक्षुता के लिए विशेष धन आवंटित किया जाता है। इन उपायों से प्रशिक्षण लागत कम करने, कार्यक्रम की गुणवत्ता में सुधार करने और अधिक कर्मचारी प्रतिधारण और वफादारी को बढ़ावा देने की उम्मीद है, जिससे व्यवसायों और अर्थव्यवस्था दोनों को लाभ होगा। राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और राष्ट्रीय शिक्षुता प्रशिक्षण योजना (एनएटीएस) जैसी सरकारी पहल उद्योगों और छात्रों दोनों को महत्वपूर्ण लाभ प्रदान करती हैं। उद्योग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप कुशल कार्यबल तक पहुंच प्राप्त करते हैं, जिससे प्रशिक्षण लागत कम हो जाती है, जबकि छात्रों को व्यावहारिक अनुभव प्राप्त होता है, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ती है और रोजगार सुरक्षित करने का मार्ग मिलता है। उद्योगों के लिए, ये योजनाएं अक्सर प्रशिक्षुता प्रशिक्षण लागतों की भरपाई के लिए सब्सिडी और अनुदान जैसे वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान करती हैं। इससे कुल खर्च कम हो जाता है और अधिक कंपनियों को भाग लेने के लिए प्रोत्साहन मिलता है। छात्रों के लिए, योजनाओं में उनकी प्रशिक्षुता के दौरान वजीफा या वेतन, मूल्यवान कार्य अनुभव प्राप्त करते समय वित्तीय सहायता प्रदान करना शामिल हो सकता है। ये वित्तीय लाभ प्रशिक्षुता को नियोक्ताओं और शिक्षार्थियों दोनों के लिए अधिक आकर्षक विकल्प बनाते हैं। निष्कर्ष नौकरी पर प्रशिक्षण के लिए कॉर्पोरेट्स के साथ साझेदारी करके प्रशिक्षुता और इंटर्नशिप के माध्यम से शिक्षा का दोहरा मॉडल भारत में एक और अग्रणी प्रवृत्ति है। छात्र संयुक्त प्रमाणपत्रों का लाभ उठाकर वास्तविक दुनिया के कार्यस्थलों में नए कौशल सीखते हैं और लागू करते हैं। इन कार्यक्रमों के पाठ्यक्रम अनुभवात्मक शिक्षा और नौकरी पर प्रशिक्षण पर केंद्रित हैं। तेजी से बढ़ती कौशल-आधारित अर्थव्यवस्था में, यह दृष्टिकोण व्यक्तियों को उनके करियर में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक दक्षताओं से लैस करने में महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे-जैसे उद्योगों का विकास जारी है, ऐसे अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रमों को एकीकृत करना एक ऐसे कार्यबल को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण रहेगा जो अनुकूलनीय, कुशल और कल की चुनौतियों के लिए तैयार हो।

-विजय गर्ग

शिक्षकों को सशक्त बनाना, भारत को सशक्त बनाना

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 और एनसीटीई कार्यक्रमों का मार्ग प्रशस्त होने के साथ, भारत ज्ञान के वैश्विक प्रतीक के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने के लिए तैयार है। 'शिक्षा केवल ज्ञान प्राप्त करने का एक तरीका नहीं है बल्कि दुनिया को बदलने का एक साधन है।' यह हमारे शिक्षक ही हैं जो इस परिवर्तन का नेतृत्व करेंगे, जिससे भारत न केवल ज्ञान की भूमि बनेगा बल्कि पूरे विश्व के लिए आशा और ज्ञान का प्रतीक बनेगा। कुछ दिन पहले मनाया गया शिक्षक दिवस, शिक्षकों द्वारा अपने पूरे करियर में किए गए निस्वार्थ योगदान की एक मार्मिक याद दिलाता है। यह छात्रों को उन लोगों के प्रति अपना आभार, प्यार और सम्मान व्यक्त करने की अनुमति देता है जिन्होंने उन्हें सच्चा नागरिक बनने के लिए मार्गदर्शन और प्रेरित किया है। यह उत्सव शिक्षकों द्वारा समाज में लाए गए अमूल्य मूल्य को पहचानने और राष्ट्र के स्तंभ के रूप में शिक्षा के महत्व पर जोर देने का एक माध्यम है। भारत अब विश्व गुरु बनने के अपने सपने को साकार करने के करीब पहुंच गया है, इस यात्रा में शिक्षण पेशा एक महत्वपूर्ण शक्ति बना हुआ है, क्योंकि भारत अपने प्राचीन पद को पुनः प्राप्त करने की राह पर है। भारत की समृद्ध शैक्षणिक विरासत इसकी संस्कृति में गहराई से निहित है, जो भारतीय शिक्षा की विरासत को दोहराती है, जहां शिक्षकों को हिंदू दर्शन में 'ब्रह्मांड के निर्माता ब्रह्मा' के समान माना जाता है। गुरु-शिष्य (शिक्षक-छात्र) रिश्ते का यह सार, जहां गुरुकुलों में ऋषियों द्वारा ज्ञान दिया जाता था, बच्चों के समग्र विकास पर जोर देता था। शिक्षकों या 'गुरुओं' का सम्मान किया जाता था, उनका दर्जा सम्राटों से भी ऊँचा होता था। भारत के नालंदा और तक्षशिला जैसे प्राचीन विश्वविद्यालय दुनिया के लिए सीखने के शुरुआती वैश्विक शिक्षण केंद्रों में से कुछ थे। भारत के प्राचीन ग्रंथ, जैसे वेद और उपनिषद, लंबे समय से दुनिया के लिए ज्ञान के स्रोत रहे हैं। जैसे-जैसे भारत ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक नेता के रूप में अपनी स्थिति पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है, शिक्षकों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है जो इस परिवर्तन के केंद्र में हैं। भारत के युवाओं के लिए शिक्षण पेशे को अपनाने का समय आ गया है; शिक्षण पेशे में निवेश करके और इसकी चुनौतियों का समाधान करके, भारत एक ऐसे भविष्य के लिए एक मजबूत आधार तैयार कर सकता है जहां वह न केवल शक्ति में, बल्कि बुद्धि और ज्ञान में भी नेतृत्व करेगा। इस प्रयास में शिक्षकों की भूमिका अपरिहार्य है, जो उन्हें भारत के उज्ज्वल भविष्य का सच्चा वास्तुकार बनाते हैं, जिज्ञासा को प्रेरित करके, आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करके और मूल्यों को स्थापित करके, वे दुनिया के भावी नेताओं को आकार दे रहे हैं। एक वैश्विक नेता के रूप में भारत के लिए प्रधान मंत्री का दृष्टिकोण केवल आर्थिक विकास या तकनीकी उन्नति के बारे में नहीं है; यह एक ऐसे समाज के निर्माण के बारे में है जहां ज्ञान, बुद्धिमत्ता और मूल्यों को महत्व दिया जाता है। जैसे-जैसे भारत विश्व गुरु बनने के अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है, शिक्षण पेशा इस दृष्टि को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। शिक्षक ज्ञान के पथप्रदर्शक होते हैं, और जब भारत विश्व गुरु बनने के अपने मिशन पर आगे बढ़ता है तो उनका सशक्तिकरण महत्वपूर्ण है। भारत की विश्व गुरु बनने की आकांक्षा उसकी शिक्षा प्रणाली के साथ गहराई से जुड़ी हुई है, जहां राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बनकर उभरी है, जो शिक्षक शिक्षा और व्यावसायिक विकास में सुधार और शिक्षण के लिए अनुकूल माहौल बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। और सीखना. नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020, जो शिक्षा के लिए अधिक लचीले, बहु-विषयक दृष्टिकोण पर जोर देती है, शिक्षकों के व्यावसायिक विकास पर एक मजबूत ध्यान केंद्रित करती है। भारत के लिएवास्तव में विश्व गुरु बनने के लिए, इसे अपने शिक्षकों में निवेश करना होगा, जो अपने अटूट समर्पण के माध्यम से देश के भविष्य के वास्तुकार के रूप में कार्य करते हैं। यहीं पर एनसीटीई उन्हें अपने पेशे में उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए आवश्यक संसाधन, प्रशिक्षण और सहायता प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एनसीटीई के प्रमुख कार्यक्रम शिक्षकों को सही समर्थन और प्रशिक्षण देकर समाज में उनकी स्थिति को ऊपर उठाने में सहायक हैं। भारत के शिक्षक निस्संदेह दुनिया के भविष्य को आकार देने में नेतृत्व करेंगे।

यह मानता है कि भविष्य के नेताओं को तैयार करने के लिए, शिक्षकों को खुद लगातार सीखते रहना चाहिए और नई शिक्षा पद्धतियों को अपनाना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं।

अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती का भारत में विदेशी निवेश पर पड़ेगा असर ? क्या कह रही सरकार

परिवहन विशेष न्यूज

बुधवार देर रात फेडरल ओपेन मार्केट कमेटी ने नीतिगत दरों को 5 .25–5 .50 प्रतिशत से 50 आधार अंकों की कटौती करके 4 .75–5 .0 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया था। हालांकि विशेषज्ञों को इससे आधी कटौती की उम्मीद थी। अखास बात यह है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का फैसला सात से नौ अक्टूबर के बीच आरबीआई की एमपीसी की होने वाली बैठक से पहले लिया गया है।

नई दिल्ली। आर्थिक मामलों के सचिव अजय सेठ ने गुरुवार को कहा कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा नीतिगत दरों में 50 आधार अंकों की कटौती से भारत में विदेशी निवेश पर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। उन्होंने कहा कि फेडरल रिजर्व ने वही किया है, जो उसे अपनी अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा लगता है। हालांकि आरबीआइ भारतीय अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर ब्याज दर में कटौती पर फैसला लेगा।

मीडिया से बात करते हुए सेठ ने कहा, 'फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती भारतीय अर्थव्यवस्था के साथ ही वैश्विक आर्थिकी के लिए भी अच्छा कदम है। ब्याज दरों के उच्चस्तर में 50 आधार अंकों की कटौती करने से नहीं लगाता है कि भारत में विदेशी निवेश पर कोई खास असर पड़ेगा। हमें यह देखना होगा कि अन्य अर्थव्यवस्थाएं कैसा व्यवहार करती हैं।'

बुधवार देर रात फेडरल ओपेन मार्केट कमेटी ने नीतिगत दरों को 5.25-5.50 प्रतिशत से 50 आधार अंकों की कटौती करके 4.75-5.0 प्रतिशत करने के लिए मतदान किया था। हालांकि विशेषज्ञों को इससे आधी कटौती की उम्मीद थी। अमेरिका के केंद्रीय बैंक ने 14 महीनों तक ब्याज दरों को दो दशक से अधिक के उच्चस्तर पर बरकरार रखा था।

खास बात यह है कि फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती का फैसला सात से नौ अक्टूबर के बीच आरबीआइ की एमपीसी की होने वाली बैठक से पहले लिया गया है। जब सेठ से यह पूछा गया कि क्या आरबीआइ ब्याज दरों में कटौती शुरू करेगा तो इस पर उनका कहना था कि एमपीसी का फैसला इस बात पर निर्भर करेगा कि भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए क्या अच्छा है।

उन्होंने कहा, 'जहां तक फेड द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बात है तो इस पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाना चाहिए। वैसे अर्थशास्त्रियों को बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि केंद्रीय बैंक रेपो रेट में किसी तरह की कमी करने का कदम उठाएगा।' आरबीई ने महंगाई पर लगाम लगाने के लिए फरवरी, 2023 से रेपो रेट को 6.50 प्रतिशत पर अपरिवर्तित रखा है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, अगस्त में सकल खुदरा मुद्रास्फीति लगातार दूसरे महीने केंद्रीय बैंक के चार प्रतिशत के लक्ष्य के नीचे 3.65 प्रतिशत रही है।

रेट कट से झूमा अमेरिकी शेयर बाजार, क्या भारतीय स्टॉक मार्केट भी होगा गुलजार?

रेट कट के फैसले पर अमेरिकी शेयर मार्केट ने गुरुवार को जबरदस्त प्रतिक्रिया दी। अमेरिका के तीनों प्रमुख सूचकांकों शुरुआती कारोबार के दौरान तेज उछाल दिखा। इससे उम्मीद की जा रही है कि शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में भी जोरदार तेजी देखने को मिलेगी। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार शुरुआती तेजी को बरकरार नहीं रख सके।

नई दिल्ली। अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने बुधवार देर रात नीतिगत ब्याज दरों में 50 बेसिस प्वाइंट यानी आधा फीसदी की कटौती की। आर्थिक जानकारों को 25 बेसिस प्वाइंट कटौती की उम्मीद थी। हालांकि, इस पर बुधवार को अमेरिकी बाजार सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं दी। रेट कट का फैसला आने के बाद अमेरिका के तीनों प्रमुख सूचकांक- Dow Jones, Nasdaq Composite और S&P 500 में रेट कट के बाद थोड़ी तेजी दिखी। लेकिन, आखिर में तीनों गिरावट के साथ बंद हुए।

हालांकि, अमेरिकी शेयर मार्केट ने रेट कट के फैसले पर असली प्रतिक्रिया आज यानी गुरुवार को दी है। शुरुआती कारोबार में तीनों प्रमुख सूचकांकों में एक से लेकर करीब 3 फीसदी तक का उछाल देख गया। गुरुवार सुबह करीब साढ़े 10 बजे (भारतीय समयानुसार शाम 8 बजे) तक Nasdaq Composite 2.79 फीसदी, S&P 500 में 1.85 फीसदी और Dow Jones Industrial Average 1.30 फीसदी तेजी के साथ कारोबार कर रहे थे। इससे पता चलता है कि निवेशकों ने रेट का जोरदार इस्तकबाल किया है।

क्या भारतीय शेयर बाजार में भी दिखेगी ?

भारतीय बाजार और निवेशक अमूमन अमेरिकी शेयर मार्केट के उतार-चढ़ाव से प्रभावित होते हैं। ऐसे में उम्मीद है कि भारतीय शेयर मार्केट में शुक्रवार को तेजी देखने को मिल सकती है। अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती के गुरुवार को भारतीय शेयर बाजार शुरुआती तेजी को बरकरार नहीं रख सके। हालांकि, अंत में यह नए रिकार्ड स्तर पर बंद होने में कामयाब रहे।

बीएसई का मानक सूचकांक सेंसेक्स 236.57 अंक की तेजी के साथ 83,184 के नए शिखर पर जाकर बंद हुआ। कारोबार के दौरान यह 825.28 अंक बढ़कर 83,773.61 के उच्च स्तर तक पहुंचा था। इसी तरह, एनएसई का निफ्टी 38.25 अंक बढ़कर 25,415.80 के सर्वकालिक उच्च स्तर पर बंद हुआ। दिनभर के कारोबार के दौरान यह 25,611.95 के उच्च स्तर तक पहुंचा था।

मालामाल हुए निवेशक, आज मिलेगा बोनस शेयर के साथ डिविडेंड

शेयर बाजार में आज रेलवे सेक्टर के शेयर पर भी निवेशकों की नजर है। आज रेलवे सेक्टर की कंपनी RITES के शेयर बढ़त के साथ कारोबार कर रहे हैं। अगर आपके पास भी RITES के शेयर हैं तो बता दें कि आज कंपनी के शेयर एक्स-बोनस और एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड कर रहा है। आइए आर्टिकल में जानते हैं कि कंपनी कितना बोनस शेयर और डिविडेंड दे रही है।

नई दिल्ली। आज रेलवे सेक्टर की कंपनी RITES के शेयर फोकस में हैं। दरअस, आज RITES के शेयर एक्स-बोनस और एक्स-डिविडेंड पर ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब है कि RITES के शेयरहोल्डर्स मालामाल हो रहे हैं। शुरुआती कारोबार से ही RITES के शेयर (RITES Share) में ही तेजी देखने को मिली है।

खबर लिखते वक्त RITES के शेयर 7.16 फीसदी की तेजी के साथ 363.55 रुपये प्रति शेयर पर ट्रेड कर रहा था।

कितना मिल रहा है बोनस शेयर (RITES Bonus Share)

स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग के अनुसार कंपनी अपने शेयरहोल्डर्स को 1:1 का बोनस शेयर दे रहा है। इसका मतलब है कि निवेशकों को 1 शेयर पर 1 शेयर मिलेगा। कंपनी ने बोनस शेयर (RITES Bonus Share) के लिए आज की तारीख तय की है। आज सुबह से कंपनी के शेयर एक्स-बोनस पर ट्रेड कर रहे हैं। जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट (Demat Account) में RITES के शेयर हैं उन्हें ही बोनस शेयर का लाभ मिलेगा।

निवेशकों को मिलेगा डिविडेंड का लाभ (RITES Dividend Stock)

RITES शेयरधारकों को आज डबल फायदा होने वाला है। दरअसल, बोनस शेयर के साथ कंपनी ने लाभांश (RITES Dividend) की भी घोषणा की है। जिन शेयरधारकों के अकाउंट में शेयर हैं उन्हें कंपनी द्वारा डिविडेंड दिया जाएगा। कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग में कहा कि वह शेयरधारकों को 5 रुपये प्रति शेयर का डिविडेंड दे रही है। कंपनी ने अभी तक यह जानकारी नहीं दी है कि शेयरधारकों के अकाउंट में किस दिन डिविडेंड क्रेडिट होगा।

RITES शेयर परफॉर्मेंस (RITES Share Performance)

RITES के शेयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले 1 साल में कंपनी के शेयर ने 28.05 फीसगी का नेगेटिव रिटर्न दिया है। वहीं बीते छह महीने में कंपनी के शेयर में 42.17 फीसदी की गिरावट आई है।

आज के लिए जारी हो गए नए रेट्स, फटाफट चेक करें कहां मिल रहा सस्ता फ्यूल

परिवहन विशेष न्यूज

ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने 20 सितंबर 2024 (शुक्रवार) के लिए फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है। रोज सुबह इनकी कीमत जारी होती है। ऐसे में गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही टंकी फुल करवाने की सलाह दी जाती है। आइए जानते हैं कि आज आपके शहर में एक लीटर पेट्रोल-डीजल कितने रुपये में मिल रहा है।

नई दिल्ली। देश की मुख्य ऑयल मार्केटिंग कंपनियां जैसे- इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL), हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (HPCL), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL) रोज सुबह 6 बजे पेट्रोल-डीजल के प्राइस अपडेट करती है। कंपनियों ने आज के लिए यानी 20 सितंबर के लिए भी फ्यूल प्राइस अपडेट कर दिया है।

आज भी सभी शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं। इसके बावजूद गाड़ीचालक को लेटेस्ट रेट चेक करने के बाद ही फ्यूल प्राइस चेक करना चाहिए क्योंकि सभी शहरों में फ्यूल के दाम अलग होते हैं। बता दें कि पेट्रोल-डीजल जीएसटी के दायरे में नहीं आता है। इस पर राज्य सरकार द्वारा वैट (Vale Added Tax) लगाया जाता है। इस वजह से सभी शहरों में इसके दाम अलग होते हैं।

HPCL की ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक, अलग-अलग शहरों में पेट्रोल-डीजल के दाम (Petrol- Diesel Price 20 September 2024)

महानगरों में पेट्रोल- डीजल के दाम

- दिल्ली में एक लीटर पेट्रोल की कीमत 94.76 रुपये और डीजल की कीमत 87.66 रुपये प्रति लीटर है।
- मुंबई में पेट्रोल की कीमत 103.43 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 89.95 रुपये प्रति लीटर है।
- कोलकाता में पेट्रोल की कीमत 104.93 रुपये प्रति लीटर और डीजल 91.75 रुपये प्रति लीटर है।
- चेन्नई में पेट्रोल की कीमत 100.73 रुपये प्रति लीटर और डीजल की कीमत 92.32 रुपये प्रति लीटर है।

देश के दूसरे शहरों में पेट्रोल- डीजल के दाम

- नोएडाः पेट्रोल 94.83 रुपये प्रति लीटर और डीजल 87.96 रुपये प्रति लीटर
- गुरुग्रामः पेट्रोल 95.19 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.05 रुपये प्रति लीटर
- बेंगलुरुः पेट्रोल 102.84 रुपये प्रति लीटर और डीजल 88.92 रुपये प्रति लीटर
- चंडीगढ़ः पेट्रोल 94.22 रुपये प्रति लीटर और डीजल 82.38 रुपये प्रति लीटर
- हैदराबादः पेट्रोल 107.39 रुपये प्रति लीटर और डीजल 95.63 रुपये प्रति लीटर
- जयपुरः पेट्रोल 104.86 रुपये प्रति लीटर और डीजल 90.34 रुपये प्रति लीटर
- पटनाः पेट्रोल 105.16 रुपये प्रति लीटर और डीजल 92.03 रुपये प्रति लीटर

डिजिटल ट्रांज़ैक्शन मोडः आईएमपीएस, आरटीजी, नएनईएफटी के मुकाबले बेस्ट है यूपीआई, यहां समझें सबकी खासियत

लेनदेन के तरीके में काफी बदलाव आया है। जहां पहले कैश से लेनदेन होता था। वहीं अब ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का दौर आ गया है। ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की बात करें तो अक्सर लोग यूपीआई (UPI) बोलते हैं। आज के समय में यूपीआई काफी पॉपुलर हो गया है। लेकिन यूपीआई के अलावा भी कई तरीके हैं जिससे फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।

नई दिल्ली। पैसों के लेनदेन के तरीके में पिछले 10 साल के भीतर काफी बदलाव देखने को मिला है। जहां पहले लोग एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करने के लिए बैंक जाते थे वह काम अब चुटकी भर में हो जाता है। जी हां, UPI, IMPS, RTG, NEFT ने पैसे के लेनदेन के तरीके को पूरी तरह से बदल दिया है। वैसे तो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के लिए आईएमपीएस ,आरटीजी, एनईएफटी जैसे मोड मौजूद हैं, लेकिन इन सब के अलावा यूपीआई काफी पॉपुलर मोड बन गया है।

अब ऑनलाइन पेमेंट के लिए लोग यूपीआई करना काफी पसंद करते हैं। यूपीआई ने एक हद तक हमारे पर्स को डिजिटल बना दिया है। अब घर से निकलने पर पॉकेट में हाथ डालकर पर्स चेक करने की जरूरत नहीं होती है। हम आपको नीचे बताएंगे कि सभी ऑनलाइन पेमेंट मोड में से यूपीआई काफी लोकप्रिय क्यों हुआ है।

NEFT

साल 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने NEFT की शुरुआत की थी। यह एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक फंड है जिसका इस्तेमाल फंड ट्रांसफर के लिए किया जाता है। बता दें कि NEFT के जरिये आसानी से एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। हालांकि, इसके लिए NEFT-इनेबल बैंक अकाउंट होना जरूरी है।

यह फंड ट्रांसफर करने का सिक्योर तरीका है। NEFT के जरिये फंड ट्रांसफर करने के लिए कस्टमर को बैंक में जाकर फॉर्म फिल करना होता है। इस फॉर्म में वह सेंडर और रिसीवर के बैंक अकाउंट की डिटेल्स देता है जिसके बाद बैंक द्वारा फंड ट्रांसफर किया जाता है।

NEFT के फायदे

- NEFT एक वन-टू-वन- पेमेंट फैसलिटी है। इसमें फंड ट्रांसफर करने के लिए थर्ड पार्टी की जरूरत नहीं होती है।
- NEFT के जरिये फंड ट्रांसफर करने के लिए बैंक द्वारा कम चार्ज लिया जाता है।
- NEFT के जरिये आधे घंटे में फंड ट्रांसफर हो जाता है।
- यह फंड ट्रांसफर करने का सिक्योर और फास्टेस्ट तरीका है।
- फंड ट्रांसफर करने के लिए कोई चेक, डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत नहीं होती है।
- NEFT के जरिये लोन, क्रेडिट कार्ड की पेमेंट भी की जा सकती है।

IMPS

IMPS भी फंड ट्रांसफर करने का इलेक्ट्रॉनिक तरीका है। IMPS का फुल फॉर्म इमेडिएट पेमेंट सर्विस है। IMPS के जरिये कस्टमर तुरंत एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर सकता है। इस सर्विस के जरिये एक बैंक में या फिर किसी दूसरे बैंक में भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।

IMPS के जरिये जो पैसे ट्रांसफर होते हैं वह रियल टाइम होता है। यानी पैसे ट्रांसफर होने में टाइम नहीं लगता है। IMPS के जरिये कितना भी फंड ट्रांसफर किया जाता है, इस पर कोई ट्रांसफर चार्ज नहीं लगता है।

IMPS के फायदे

- इसके जरिये आधार नंबर और मोबाइल नंबर के जरिये भी फंड ट्रांसफर किया जा सकता है।
- यह फंड ट्रांसफर करने का फास्ट, सेफ और सिक्योर तरीका है।
- IMPS में फंड ट्रांसफर करने की कोई लिमिट नहीं होती है।
- बैंक हॉलिडे वाले दिन भी IMPS सर्विस चालू रहती है।
- नेट बैंकिंग, एटीएम, मोबाइल फोन से आसानी से IMPS की सर्विस का लाभ उठाया जा सकता है।
- IMPS से पेमेंट के लिए बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड आदि जानकारी की जरूरत नहीं होती है।
- IMPS में रियल टाइम फंड ट्रांसफर या सेटलमेंट होता है।

RTGS

RTGS जिसे रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट भी कहते हैं। इसमें भी आप कितनी भी राशि ट्रांसफर कर सकते हैं। RTGS की शुरुआत 1985 में 3 सेंट्रल बैंक के जरिये हुई थी। आरबीआई ने 2004 में इसे भारत में लॉन्च किया था। आज 72 से ज्यादा बैंकों में RTGS की सुविधा मिलती है। इसमें भी लेनदेन की कोई अधिकतम और न्यूनतम लिमिट नहीं होती है।

RTGS के फायदे

- RTGS से ऑनलाइन और ऑफलाइन पेमेंट की जा सकती है।
- इसमें पेमेंट को शेड्यूल भी किया जा सकता है।
- RTGS की सर्विस 24X7 उपलब्ध है। यानी कभी भी पेमेंट किया जा सकता है।
- यह वन-टू-वन क्रेडिटिंग सिस्टम है।

UPI

सरकार द्वारा शुरू की गई 'Digital India' अभियान में यूपीआई की अहम भूमिका है। यह कैशलेस ट्रांजैक्शन को पूरी तरह से बढ़ावा दे रहा है। आज भारत ही नहीं दुनिया के कई देशों में यूपीआई का इस्तेमाल होता है। आरबीआई और एनपीसीआई (NPCI) ने साल 2016 में यूनिफाइड इंटरफेस पेमेंट (UPI) को लॉन्च किया था। यूपीआई के जरिये पेमेंट करना काफी आसान है। इस वजह से लोगों के बीच यह काफी पॉपुलर है।

यूपीआई की लोकप्रियता इस बात से साबित हो जाती है कि एक महीने में 10 लाख से ज्यादा यूजर यूपीआई के जरिये पेमेंट करते हैं। अब पटरी की दुकानों से लेकर मॉल के शोरूम तक यूपीआई ने अपनी धाक जमा ली है।

UPI के फायदे

- सिंगल क्लिक के जरिये आसानी से यूपीआई पेमेंट की जा सकती है।
- यूपीआई के जरिये पेमेंट भी की जा सकती है और रिसीव भी किया जा सकता है।
- यूपीआई यूजर एक दिन में 1 लाख रुपये तक की पेमेंट कर सकते हैं।
- यूपीआई आईडी के माध्यम से आसानी से कहीं भी पेमेंट की जा सकती है।
- ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से यूपीआई पेमेंट किया जा सकता है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और गति शक्ति: आज की भारतीय अर्थव्यवस्था और उभरते लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में महत्वपूर्ण भूमिका

डॉ.लॉजिस्टिक्स

भारतीय अर्थव्यवस्था के तेज़ी से बढ़ते विकास में लॉजिस्टिक्स का अहम योगदान है। हाल के वर्षों में, लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को मजबूत और व्यवस्थित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति (National Logistics Policy - NLP) और गति शक्ति योजना इस दिशा में क्रांतिकारी पहल हैं। इन नीतियों का उद्देश्य भारत को वैश्विक सप्लाई चेन में मजबूती प्रदान करना और लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे का निर्माण करना है।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति की परिभाषा और उद्देश्य

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति का लक्ष्य है भारत के लॉजिस्टिक्स क्षेत्र को अधिक कुशल, किफायती और प्रतिस्पर्धी बनाना। इस नीति के तहत देश में लॉजिस्टिक्स से जुड़ी लागत को कम करना, ट्रांसपोर्टेशन के समय को घटाना और सप्लाई चेन के सभी घटकों को डिजिटल रूप से एकीकृत करना प्रमुख उद्देश्य हैं।

भारत में लॉजिस्टिक्स की उच्च लागत ने लंबे समय से उद्योगों को प्रभावित किया है, जिससे उत्पादों की कीमतों में वृद्धि होती है और वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता कम होती है। NLP के तहत, 2030 तक भारत की लॉजिस्टिक्स लागत को GDP के 8% तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। इससे न केवल घरेलू उद्योगों को लाभ होगा बल्कि विदेशी निवेश और व्यापार में भी वृद्धि होगी।

गति शक्ति योजना का महत्व

प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना का उद्देश्य भारत के बुनियादी ढांचे को एकीकृत और सुव्यवस्थित करना है। यह योजना एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से 16 मंत्रालयों को एक साथ लाने का कार्य करती है, ताकि सड़कों, रेल, एयरपोर्ट, बंदरगाह और वॉटरवेज़ के माध्यम से एक समग्र मल्टी-मोडल परिवहन नेटवर्क तैयार किया जा सके। यह नेटवर्क लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन के बीच की बाधाओं को खत्म कर, उन्हें तेज़ और अधिक कुशल बनाएगा।

गति शक्ति योजना के तहत, बुनियादी ढांचे के विकास में तेजी लाई जा रही है, जिससे माल की आवाजाही में समय की बचत होगी। यह योजना आर्थिक और औद्योगिक क्षेत्रों को और बेहतर बनाने के साथ-साथ कृषि, निर्माण, ऊर्जा, और सेवा क्षेत्रों को भी अधिक लाभकारी बनाएगी।

भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लाभ

भारत में बढ़ते ई-कॉमर्स, विनिर्माण, और व्यापार के कारण लॉजिस्टिक्स क्षेत्र का महत्व और भी बढ़ गया है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और गति शक्ति योजना के तहत हो रहे बुनियादी ढांचे के विकास से निम्नलिखित लाभ हो रहे हैं:

लागत में कमी: लॉजिस्टिक्स लागत को कम करने से उत्पादों की कीमतें घटेंगी और भारतीय कंपनियाँ वैश्विक स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होंगी।

रोज़गार के अवसर: इन योजनाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे और लॉजिस्टिक्स क्षेत्रों में रोजगार के नए अवसर उत्पन्न हो रहे हैं, विशेषकर छोटे शहरों और ग्रामीण क्षेत्रों में।

कृषि उत्पादों का बेहतर परिवहन: गति शक्ति योजना के तहत मल्टी-मोडल परिवहन से कृषि उत्पादों को तेज़ी से बाजारों तक पहुंचाया जा सकेगा, जिससे किसानों को अधिक मुनाफा मिलेगा।

पर्यावरणीय लाभ: लॉजिस्टिक्स के डिजिटलाइजेशन और मल्टी-मोडल परिवहन से ईंधन की खपत में कमी आएगी और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

लॉजिस्टिक्स सेक्टर की वृद्धि और भविष्य

भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र आने वाले वर्षों में और भी तेजी से बढ़ेगा। सरकार द्वारा उठाए गए इन कदमों से लॉजिस्टिक्स कंपनियों को नई तकनीकों और डिजिटल समाधानों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आधुनिक तकनीक और डेटा एनालिटिक्स का उपयोग सप्लाई चेन को और अधिक कुशल बनाएगा।

राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति और गति शक्ति योजना भारतीय लॉजिस्टिक्स क्षेत्र के लिए एक नई दिशा प्रदान कर रही हैं। इन योजनाओं के सफल कार्यान्वयन से न केवल भारतीय उद्योगों को लाभ होगा, बल्कि भारत वैश्विक सप्लाई चेन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इन नीतियों के माध्यम से भारत लॉजिस्टिक्स के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों को छूने के लिए अग्रसर है और यह निश्चित रूप से भारत को एक रविश्वगुरुर के रूप में स्थापित करने में मदद करेगा।

डॉ. अंकुर शरण, लॉजिस्टिक्स विशेषज्ञ
drlogistics.ankur@gmail.com

'दूध और मछलीपालन के सेक्टर को संगठित करने की जरूरत', बोले केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह

केंद्रीय मत्स्यपालन पशुपालन डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह ने शुक्रवार को गोवा के नोवोटेल रिसोर्ट में सीएलएफएमए ऑफ इंडिया (क्लेफमा) के 65वें राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आज सरकार के पहल से भारत विश व में पशु धन मामले में पहले नंबर पर है और दूध का उत पादन लगातार बढ़ रहा है।

गोवा। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने कहा कि आज सरकार के पहल से भारत विश्व में पशु धन मामले में पहले नंबर पर है। दूध का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। दूध का बाजार 11.16 मिलियन का है। ग्लोबल ग्रोथ 6 फीसदी की दर से बढ़ रहा है, जबकि विश्व में यही 2 फीसदी है। प्रति व्यक्ति खपत 459 ग्राम जबकि विश्व में 325 ग्राम है। यही खपत 2013-14 में 307 ग्राम प्रति व्यक्ति थी, जो बढ़ कर 459 ग्राम तक पहुंच गया है। उन्होंने बताया कि इसी तरह अंडे का बाजार 78 मिलियन का था, आज 138 मिलियन के करीब है। यह केन्द्र सरकार के प्रयास से हो रहा है। मछली का 60 हजार करोड़ का निर्यात है, वहीं दूध में मुनाफा डेढ़ गुना बिचौलिये खा जाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण यह सेक्टर के बड़े हिस्से का असंगठित होना है। आज इस सेक्टर को संगठित सेक्टर बनाने की जरूरत है, जिससे दूध उत्पादन करने वाले किसानों को पूरा का पूरा लाभ मिल सके।

क्लेफमा के 65वें राष्ट्रीय सम्मेलन में पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री

राजीव रंजन ने कहा कि इसके अलावा पशुपालन के क्षेत्र में घरेलू समाधानों को बढ़ावा देने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए केंद्र सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिनके तहत भारतीय नस्लों में आनुवांशिक सुधार के लिए आईवीएफ की नई तकनीक विकसित की गई है। केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन, डेयरी एवं पंचायती राज मंत्री शुक्रवार को गोवा के नोवोटेल रिसोर्ट में सीएलएफएमए ऑफ इंडिया (क्लेफमा) के 65वें राष्ट्रीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे।

वन नेशन-वन इलेक्शन राष्ट्रहित में सरकार का महत्वपूर्ण फैसला : वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा

परिवहन विशेष न्यूज

आगरा। वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को कैबिनेट की भी मंजूरी मिल गई है। सरकार अब इसे शीतकालीन सत्र में बिल के रूप में पेश कर सकती है। हालांकि इसे लागू करने के लिए पहले संविधान संशोधन और सभी राज्यों की मंजूरी की भी जरूरत होगी।

वन नेशन-वन इलेक्शन बिल को वरिष्ठ समाजसेवी डॉ उमेश शर्मा ने महत्वपूर्ण कदम बताते हुए कहा, वन नेशन-वन इलेक्शन देश की आवश्यकता है। हर वर्ष किसी न किसी राज्य में चुनाव होते रहते हैं। चुनावों की इस निरंतरता के कारण देश हमेशा चुनावी मोड में रहता है। इससे न केवल प्रशासनिक और नीतिगत निर्णय प्रभावित होते हैं बल्कि देश के खजाने पर भारी बोझ भी पड़ता है। वन नेशन-वन इलेक्शन से गरीब मतदाताओं को भी सुविधा होगी। क्योंकि देश में हर समय जो कोई ना कोई चुनाव होता रहता है। उससे ना केवल खर्च बढ़ता है, बल्कि ग़रीब मतदाताओं में भी उदासीनता आती है। आचार संहिता लगने के कारण विकास कार्यों को भी रोकना पड़ता है और लोगों की ऊर्जा खर्च होती है। इस ऊर्जा को लोगों के विकास और कल्याण के लिए लगाया जा सकता हैं। इससे केंद्र और राज्य के प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सभी भारतीय लोकसभा और विधानसभा चुनावी में मतदान करेंगे। यही नहीं इसके लागू होते ही नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव भी साथ होंगे। एक देश एक चुनाव लागू होते ही संसाधनों की भी बचत होगी। प्रधानमंत्री मोदी कैबिनेट के इस फैसले का हम स्वागत करते हैं। राष्ट्रहित में सभी राजनीतिक दल और देश के लोग इसका स्वागत करना चाहिए। वन नेशन-वन इलेक्शन सभी को मिलकर समर्थन करना चाहिए।

श्री शर्मा ने आगे कहा, वन नेशन-वन इलेक्शन हमारे देश की लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और सशक्त बनाएगा, चुनावी खर्च कम करेगा और विकास कार्यों में तेजी लाएगा। साथ ही, चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी कोष पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और हमेशा होने वाले चुनाव देश की प्रगति में बाधक भी नहीं होंगे। जगह जगह अलग अलग चुनाव होने से देश में 24 घंटे चुनाव की तैयारी चलती रहती है। इसलिए विकास के बड़े फैसले नहीं लिए जा पाते और कीमती समय भी खर्च होता हैं। इससे देश और जनता को फायदा होगा। जैसा कि सभी जानते हैं कि आजादी के बाद देश में सारे चुनाव एक साथ ही होते थे। वन नेशन-वन इलेक्शन आयोजित करने से महत्वपूर्ण समय और व्यय बच सकता है, प्रशासनिक दक्षता बढ़ सकती है और संभावित रूप से मतदाता मतदान बढ़ सकता है। इसके अतिरिक्त, सुरक्षा कर्मियों की बार- बार तैनाती और स्थानांतरण से जुड़ी समस्याओं से राहत मिलेगी। वन नेशन-वन इलेक्शन से देश की तोकतांत्रिक प्रक्रिया सशक्त होंगी साथ ही चुनावों में पारदर्शिता बढ़ेगी और सरकारी कोष पर पड़ने वाला आर्थिक बोझ कम होगा और विकास कार्यों में तेजी लाएगा।

मणिपुर में उग्रवादी संगठन के तीन कैडर गिरफ्तार, हथियार बरामद; मंत्री के निजी सहायक का अपहरण

मणिपुर के उपभोक्ता मामलों के मंत्री एल. सोमोरेंद्रो के निजी सहायक 43 वर्षीय एस. सोमोरेंद्रो का इंफाल पूर्वी जिले में शुक्रवार को उनके आवास से अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने कहा किसी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और जांच की जा रही है। इससे पहले सशस्त्र हमलावरों ने गुरुवार रात बिष्णुपुर जिले में पूर्व मुख्य सचिव ओइनाम नाबाकिशोर के आवास पर पांच राउंड फायरिंग की।

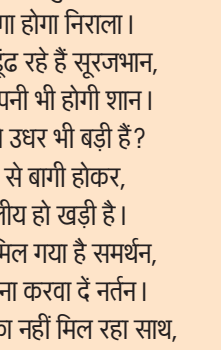

इंफाल : मणिपुर के उपभोक्ता मामलों के मंत्री एल. सोमोरेंद्रो के निजी सहायक 43 वर्षीय एस. सोमोरेंद्रो का इंफाल पूर्वी जिले में शुक्रवार को उनके आवास से अज्ञात लोगों ने अपहरण कर लिया। पुलिस ने कहा कि किसी समूह ने इसकी जिम्मेदारी नहीं ली है और जांच की जा रही है।

इससे पहले सशस्त्र हमलावरों ने गुरुवार रात बिष्णुपुर जिले में पूर्व मुख्य सचिव ओइनाम नाबाकिशोर के आवास पर पांच राउंड फायरिंग की। दूसरी ओर सुरक्षा बलों ने इंफाल पश्चिमी और इंफाल पूर्वी जिलों में अगल-अलग अभियानों में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन के तीन कैडरों को गिरफ्तार किया।

बरामद हुए कई हथियार और गोलियां

उग्रवादियों से कई आइईडी, हथियार और गोलियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने बताया कि तीनों कैडर कांग्लेई यावोल कंबा लुप के हैं।

मेजर की बाधाबी से दुष्कर्म की घटना। विपक्षी दल के नेता नवीन पटनायक ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की

मनोरंजन सासमल , स्टेट हेड ओड़िशा

भुबनेश्वर: भरतपुर थाने में मेजर की बाधाबी से दुष्कर्म की घटना। विपक्षी दल के नेता बिजेड़ी सुप्रीमो नवीन पटनायक ने घटना की न्यायिक जांच की मांग की है। मेजर के बाधाबी का यौन उत्पीड़न किया गया है। हमले की घटना से गहरा दुख पहुंचा है। नवीन ने कहा कि घटना बेहद निंदनीय है।ओडिशा रिटायर आर्मी एसोसिएशन के मुताबिक, मेजर गुरवश सिंह और उनके बंधवी पर शनिवार देर रात बदमाशों ने हमला कर दिया। कांस्टेबल से लेकर पुलिस अधिकारी तक सभी उसे प्रताड़ित करने के लिए एकजुट हो गए। यहां तक कि वह उसका यौन उत्पीड़न करने से भी नहीं हिचकिचाया। पुलिस की पिटाई से वह गंभीर रूप से घायल हो गया। मारपीट में उनका एक हाथ टूट गया और दांत भी टूट गये. खास तौर पर उनकी छाती और पीठ पर काफी चोट लगी थी, लेकिन उनकी उचित जांच की गई और अदालत में लाकर जेल भेज दिया गया। जमानत मिलने के बाद कल शाम उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। मीडिया में अंकिता के बयान के बाद पूरे राज्य में तीखी प्रतिक्रिया हुई। पूर्व सैनिक संघ ने घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। इतना ही नहीं आरोपी पुलिस कर्मियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की मांग की गई।इस घटना में निलंबित आईआईसी दिनकृष्ण मिश्रा समेत भरतपुर के अन्य निलंबित पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर लिया है। संगीत विभाग में यौन उत्पीड़न के तौर पर मामला दर्ज किया गया है. क्राइम ब्रांच ने मेजर गुरबंस सिंह की लिखित रिपोर्ट के आधार पर मामला दर्ज किया है। पूर्व आइआइसी दिनकृष्ण मिश्र व उनके साथी से अपराधी के रूप में पूछताछ की गयी है। कल, मेजर के बहनोई घातक शिकायत लेकर आए। पुलिस की बर्बरता के बारे में बात करते हुए वह फूट-फूटकर रो पड़े। पुलिस की बर्बरता चरम सीमा पर पहुंचने की खबर के बाद क्राइम ब्रांच ने आपराधिक मामला दर्ज किया है।

युवा शक्ति को नशे की बुराई से बचना होगा

नशा समाज के लिए नासूर बन गया है यह एक घातक बुराई है जो हमारे जीवन के अनमोल लम्हों को तबाह कर देती है। नशे की यह बुराई बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर देती है। मानवीय मूल्यों के समीकरण को बिगड़ देती है।यह आधुनिकता की इस दुनिया में युवा पीढ़ी नशे की गुलाम बन गई है। यह नये जमाने में मनुष्य का मूलतत्व ही ख़तरे में है युवा जो भारत की सबसे बड़ी शक्ति है अगर वही नशे में लिप्त हो जायेगी तो भविष्य अंधकारमय हो जायेगा। आधुनिक युग में फैशन के चक्कर में युवाओं के कदम बहक गए हैं। तभी तो लड़के लड़कियां खुले आम सिगरेट के धुंए में हर एक चिंता को धुंए में उड़ा रहे हैं वह बहुत ही नासमझी वाला फैसला ले रहे हैं। धुंए ने उनके जीवन को खराब कर दिया है । नशा कैसा भी हो वह समाज के लिए खासकर मनुष्य जीवन के लिए जहर के समान है इससे दूर रहेना ही होगा। आज कल खुले आम पब कल्चर का बोलबाला है वहीं केफे भी आजकल आधुनिक ठिये बनाते जा रहें हैं। नशीली चीजें बहुत आसानी से मिल जाया करती है सरकार को इन नशीली चीजों से सबसे ज्यादा राजस्व मिलता है। तो नशे पर प्रतिबंध लगाने की बात तो दूर की कौड़ी हों चुकी है। अगर मानवीय मूल्यों से देखें तो यह नशा भविष्य की नींव को दीमक की तरह खा रहा है। देर रात शहरों में शराबखोरी का रंग देखा जाता है नौजवान युवक युवतियां किस प्रकार सारी हदें पार कर देते हैं। वह नशे की हालत में वह अपने वाहनों में किस तरह डगमगाते हुए जाते हैं । तभी तो दुघर्टनाओं को

वह बुलावा देते हैं बेचारे बेकसूर लोग मौत के मूंह में चलें जातें हैं। पैसे वालों को नशे की लत इस कदर हावी है कि उसी से नशे का करोबार फल-फूल रहा है। कितनी बड़ी विडंबना है कि जहां नशे पर प्रतिबंध लगा है उस राज्यों में सबसे ज्यादा अवैध रूप से नशाखोरी होती है बहुत से राज्य नशे के मकड़जाल में डुब चुके हैं। समाजिक स्तर पर व राजनितिक पहेलू पर सिर्फ बातें होती है। नशे के खिलाफ युवा शक्ति को बचाने के लिए ठोस व निर्णायक पहलू पर पहल कब होगी? युवा पीढ़ी को नशे की बुराई से बचना ही होगा, अगर अभी भी नहीं जागे तो बहुत देर हो जायेगी। नशे में भारत का युवा अपने कदमों को बहका रहा है और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शराब सिगरेट बीड़ी ड्रग्स चरस गांजा भांग आदि सभी नशीली चीजों से गुमनामी के अंधेरे में नौजवानों के कदम लड़खड़ा रहे हैं इन्हें हमें बचाना होगा। कब तक इस तरह नशे के गुलाम बनाते युवा पीढ़ी को देखते रहेंगे। वर्तमान में बहुत सी घातक बिमारियों का शिकार युवा वर्ग नशें के कारण हो रहे है । इसलिए उन्हें नशे से मुक्ति दिलाने हेतु समाजिक पहल व जनचेतना को जागरूक करने की बहुत ज्यादा जरूरत है समाज अगर नशे की बुराई के खिलाफ एकजुट हो जाएं तो सरकारें भी जाग जायेंगी।

हरिहर सिंह चौहान
इन्दौर 9826084157

कविता : कौन नहीं है मुश्किल में?

ताऊ बोल्या कौन नहीं है मुश्किल में?
अब सैनी पर है सबकी पैनी नजर,
त्रिकोणीय मुकाबले में फस्यो हैं होगा असर।
हुड्डाजी की है शैलजा पर कड़ी नजर,
उन्हें समझ नहीं आता कैसे तय होगा,
इनका मुख्यमंत्री बनने का सफर?
क्या? शैलजा का साथ देंगे सुरजेवाला,
कभी तो मौसम बदलेगा होगा निराला।
पोस्टरों में अपनी फोटो ढूंढ रहे हैं सूरजभान,
जब जीतेगी पार्टी तब अपनी भी होगी शान।
ताऊ बोल्या मुश्किल तो उधर भी बड़ी हैं?
देखों तो सही भाजपा से बागी होकर,
सावित्री जिंदल निर्दलीय हो खड़ी है।
उन्हें सुभाष चंद्रा का भी मिल गया है समर्थन,
उन्हें कहीं आलाकमान ना करवा दें नर्तन।
कमल (गुप्ता) को कमल का नहीं मिल रहा साथ,
तीज-त्योहार पर भी उन्हें नहीं किया याद?
चंद्राजी भला कैसे दे दे अपना आशीर्वाद?
आखिर, ताऊ बोल्या सब का सब है मुश्किल में?

संजय एम. तराणेकर
(कवि, लेखक व समीक्षक)
31, संजय नगर, इंदौर
(मध्यप्रदेश)
98260-25986

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक संजय कुमार बाटला द्वारा इम्प्रेशंस प्रिंटिंग एंड पैकेजिंग लिमिटेड, सी-18,19,20 सेक्टर 59, नोएडा (उत्तर प्रदेश) से मुद्रित एवं 3, प्रियदर्शनी अपार्टमेंट ए-4, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली- 110063 से प्रकाशित। सम्पर्क : 9212122095, 9811902095. newstransportvishesh@gmail.com
(इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी) किसी भी कानूनी विवाद की स्थिति में निपटारा दिल्ली के न्यायालय के अधीन होंगे। RNI No :- DELHIN/2023/86499. DCP Licensing Number F.2 (P-2) Press/2023